वीकली वन लाइनर्स 20 से 26 जुलाई, 2026

BHAVYA Rasayan Scheme क्या है? कैबिनेट ने नई केमिकल पार्क्स पहल स्कीम को मंज़ूरी दी

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली यूनियन कैबिनेट ने भारत औद्योगिक विकास योजना रसायन (BHAVYA Rasayan) स्कीम को मंज़ूरी दे दी है। यूनियन बजट 2026–27 में पेश की गई इस स्कीम का मकसद पूरे भारत में एडवांस्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ तीन खास केमिकल पार्क बनाना है। इस स्कीम का कुल फाइनेंशियल खर्च ₹3,030 करोड़ है। इस प्रोग्राम से केमिकल इंडस्ट्री में भारत की कॉम्पिटिटिव पोजीशन बढ़ने, देश और विदेश के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने, नौकरी के मौके बनाने और विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर भारत को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

भव्य रसायन योजना क्या है?

BHAVYA रसायन स्कीम केंद्र सरकार की एक पहल है, जिसका मकसद केमिकल इंडस्ट्री के लिए ज़रूरी कॉमन इंफ्रास्ट्रक्चर और यूटिलिटीज़ के साथ तीन केमिकल पार्क बनाना है।

इस पहल का मकसद ऐसे इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम बनाना है जो अपस्ट्रीम से लेकर डाउनस्ट्रीम और सहायक इंडस्ट्रीज़ तक, पूरी केमिकल वैल्यू चेन को पूरा कर सकें।

सरकार का इरादा शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर शुरू करके केमिकल सेक्टर में प्रोडक्शन कॉस्ट कम करना और एफिशिएंसी बढ़ाना है।

रसायन योजना की मुख्य विशेषताएं

BHAVYA रसायन स्कीम की खास बातें नीचे दी गई हैं,

- 24 जुलाई, 2026 को केंद्रीय कैबिनेट ने मंज़ूरी दी।
- FY 2026-2027 के यूनियन बजट में इसकी घोषणा की गई।
- ₹3,030 करोड़ का फ़ाइनेंशियल खर्च देना।
- इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए ₹3,000 करोड़।
- एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च पर ₹30 करोड़।
- स्कीम का समय FY 2026 से FY 2031 तक है।
- तीन केमिकल पार्क बनाए जाएंगे।
- केंद्र से हर पार्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मदद ₹1,000 करोड़ होगी।
- राज्य सरकार का कम से कम योगदान ₹500 करोड़ होगा।
- पार्क का चयन चैलेंज रूट से किया जाएगा।

वित्तपोषण ढांचा

यह पहल को-फंडेड मॉडल पर चलती है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार दोनों के फंड का इस्तेमाल किया जाता है।

वित्तीय सहायता

- केंद्र सरकार से मदद: हर केमिकल पार्क के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ₹1,000 करोड़।
- राज्य सरकार का योगदान: कम से कम ₹500 करोड़।
- कुल अनुमानित व्यय: ₹3,030 करोड़।

इस जॉइंट फंडिंग सिस्टम के ज़रिए मकसद राज्यों को आगे आकर अच्छा इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए काम करने के लिए मोटिवेट करना है।

केमिकल पार्कों में इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा

हर केमिकल पार्क में प्लग-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जिससे इंडस्ट्रीज़ के लिए पार्क में अपना ऑपरेशन सेट अप करना आसान हो जाता है।

- सामान्य बुनियादी ढांचा सुविधाएं
- सामान्य अपशिष्ट उपचार संयंत्र (सीईटीपी)
- उपचार, भंडारण और निपटान सुविधा (टीएसडीएफ)
- खतरनाक अपशिष्ट प्रबंधन सुविधा
- जल आपूर्ति और वितरण प्रणाली
- भाप उत्पादन और वितरण प्रणाली
- विलायक पुनर्प्राप्ति और आसवन सुविधाएं
- परस्पर जुड़ी पाइपलाइन प्रणाली
- रसद और भंडारण सुविधा

सुविधाओं को शेयर करने से इंडस्ट्री को एनवायरनमेंटल नियमों का पालन करके ऑपरेशनल कॉस्ट बचाने में मदद मिलेगी।

पात्रता और भूमि आवश्यकताएँ

इस प्रोग्राम के तहत, राज्य सरकारें केमिकल पार्क बनाएंगी।

बुनियादी आवश्यकताएं

- कम से कम 8 sq.km (लगभग 2000 एकड़) ज़मीन, जिस पर कोई कब्ज़ा न हो और जो आपस में सटी हो।
- कॉम्पिटिटिव चैलेंज रूट के आधार पर सिलेक्शन के लिए एलिजिबिलिटी।
- विकास के लिए केंद्र सरकार के साथ सहयोग।

इन बड़े इंटीग्रेटेड पार्कों में कई केमिकल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी और उससे जुड़ी इंडस्ट्री होने की संभावना है।

रसायन योजना का उद्देश्य

इस स्कीम का मकसद सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट और इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाकर भारत में केमिकल इंडस्ट्री के डेवलपमेंट को बढ़ाना है।

मुख्य उद्देश्य

- इंटीग्रेटेड केमिकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देना।
- लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करना। मैन्युफैक्चरिंग खर्च में कमी।
- अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम दोनों कंपनियों को मजबूत करना।
- देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना।
- इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए इंसेंटिव देना।
- एक्सपोर्ट का लेवल बढ़ाना।
- घरेलू और विदेशी निवेश आकर्षित करना।
- पर्यावरण की सस्टेनेबिलिटी बढ़ाना।
- नौकरियां बनाना।

भारत के केमिकल सेक्टर के लिए फ़ायदे

केमिकल सेक्टर कई मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के काम करने के लिए बहुत ज़रूरी है।

उम्मीद है कि BHAVYA रसायन स्कीम लंबे समय में फायदेमंद साबित होगी।

बढ़ी हुई प्रतिस्पर्धा

शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर से खर्च काफी कम हो जाएगा और विदेशी मार्केट में भारतीय मैन्युफैक्चरर्स की प्रोडक्टिविटी और कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगी।

Test Prime By Adda247

ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION

Test. Analyze. Improve. Repeat.

Don't just prepare. Perform.

Test Prime – built only for mock tests.

1,50,000+ Mock Tests

25,000+ Previous Year Papers

800+ Exam Covered

500% Refund on Selection

5 lakh+ Free Quizzes

Daily Free PDFs

Top Alerts Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- Multilingual
- Detailed Solution
- Strong and Weak Areas
- All India Rankings

- Safe & Reliable
- Trusted by Lakhs of Aspirants
- Your Success, Our Mission

DOWNLOAD TEST PRIME

Your Success Partner!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

ग्लोबल वैल्यू चेन के अंदर बेहतर इंटीग्रेशन

इस स्कीम का मकसद ग्लोबल केमिकल सप्लाई चेन में भारत का स्टेटस बेहतर करना और दूसरे देशों से केमिकल सामान पर डिपेंडेंस को कम करना है।

सतत औद्योगिक विकास

सेंट्रलाइज़्ड वेस्ट डिस्पोज़ल सिस्टम और एनवायरनमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ़ और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में मदद करेंगे।

रोजगार को बढ़ावा देना

बड़े केमिकल पार्क शुरू होने से मैन्युफैक्चरिंग, लॉजिस्टिक्स वगैरह में कई नौकरियां पैदा होने की उम्मीद है।

FIFA वर्ल्ड कप 2026 अवार्ड्स: विजेताओं की पूरी लिस्ट

2026 का FIFA वर्ल्ड कप खत्म हो गया, और स्पेन को अर्जेंटीना के खिलाफ एक्स्ट्रा टाइम में 1-0 के स्कोर से मैच जीतने के बाद टाइटल होल्डर का ताज पहनाया गया। FIFA ने टूर्नामेंट में हिस्सा लेने वालों के लिए अपने जाने-माने इंडिविजुअल अवॉर्ड्स की घोषणा की है। ज़्यादातर ट्रॉफी टूर्नामेंट के विनर्स - स्पेन ने जीतीं, जहाँ रोड्री और उनाई सिमोन को उनकी कामयाबियों के लिए बड़े अवॉर्ड्स मिले, जबकि काइलियन एम्बाप्पे ने गोल्डन बूट जीतकर यह साबित कर दिया कि वह दुनिया के बेस्ट स्कोरर्स में से एक हैं। इन अवॉर्ड्स से टूर्नामेंट में प्लेयर्स और उनकी कामयाबियों को परखने में मदद मिली।

FIFA वर्ल्ड कप 2026 अवार्ड्स में स्पेन विजयी

वर्ल्ड कप में अपनी शानदार जीत के बाद स्पेन FIFA वर्ल्ड कप 2026 अवॉर्ड्स में सबसे बड़ा विजेता बनकर उभरा है।

देश को वर्ल्ड कप में स्पेन के शानदार प्रदर्शन में अहम भूमिका निभाने वाले तीन खिलाड़ियों के लिए तीन अलग-अलग अवॉर्ड मिले।

स्पेन ने न सिर्फ़ टूर्नामेंट जीता, बल्कि पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ़ एक गोल खाया, जिससे उसने सबसे कम गोल खाने का रिकॉर्ड तोड़ दिया।

ये अवॉर्ड स्पेन के कोच लुइस डे ला फुएंते की लीडरशिप में डिफेंसिव ताकत, मिडफील्ड कंट्रोल और टैक्टिकल डिसिप्लिन के शानदार बैलेंस की वजह से मिले।

रोड्री ने एडिडास गोल्डन बॉल हासिल की

स्पैनिश फुटबॉलर रोड्री को कॉम्पिटिशन का टॉप प्लेयर होने के लिए एडिडास गोल्डन बॉल से सम्मानित किया गया।

रोड्री ने पूरे कॉम्पिटिशन में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। बॉल कंट्रोल, सटीक पासिंग, अलर्ट डिफेंस और शानदार लीडरशिप में उनकी बेहतरीन स्किल्स स्पेन के टूर्नामेंट में खेले गए सभी आठ गेम में दिखीं।

उनके शानदार प्रदर्शन की वजह से स्पेन को दूसरा FIFA वर्ल्ड कप टाइटल जीतने में मदद मिली।

गोल्डन बॉल विजेता

- गोल्डन बॉल: रोड्री (स्पेन)
- सिल्वर बॉल: लियोनेल मेस्सी (अर्जेंटीना)
- कांस्य पदक: किलियन एमबाप्पे (फ्रांस)

किलियन एमबाप्पे को गोल्डन बूट मिला

हालांकि फ्रांस कुल मिलाकर चौथे स्थान पर रहा, लेकिन काइलियन एमबाप्पे ने एक बार फिर दिखा दिया कि उन्हें दुनिया के सबसे अच्छे फॉरवर्ड में क्यों गिना जाना चाहिए।

उन्होंने कॉम्पिटिशन के दौरान सबसे ज़्यादा गोल किए, जो आठ मैचों में 10 थे, और टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर के तौर पर एडिडास गोल्डन बूट जीता।

नेट के सामने उनके ज़बरदस्त प्रदर्शन ने इतिहास रच दिया, क्योंकि वे लगातार दो बार वर्ल्ड कप गोल्डन बूट जीतने वाले अकेले खिलाड़ी बन गए।

उनके नाम पुरुषों के FIFA वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में अब तक के सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी होने का रिकॉर्ड भी है, उन्होंने अपने करियर में 22 गोल किए हैं।

गोल्डन बूट के लिए मुख्य खिलाड़ी

- गोल्डन बूट: किलियन एमबाप्पे (फ्रांस) – 10 गोल
- सिल्वर बूट: लियोनेल मेस्सी (अर्जेंटीना) – 8 गोल
- ब्रॉन्ज़ बूट: जूड बेलिंगहम (इंग्लैंड) – 7 गोल

उनाई सिमोन ने गोल्डन ग्लव जीता

स्पेन की नेशनल टीम के गोलकीपर उनाई सिमोन को FIFA वर्ल्ड कप में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए एडिडास गोल्डन ग्लव ट्रॉफी से सम्मानित किया गया।

साइमन फाइनल में अर्जेंटीना के खिलाफ नेट क्लीन रखते हुए पूरे टूर्नामेंट में कुल सात क्लीन शीट हासिल करने में कामयाब रहे, जिससे स्पेन के शानदार डिफेंस रिकॉर्ड में काफी मदद मिली।

सिमोन ने लगभग 650 मिनट तक कोई गोल न खाने का एक शानदार रिकॉर्ड बनाया, जिससे इस टूर्नामेंट में स्पेनिश डिफेंस का दबदबा दिखा।

पाऊ क्यूबार्सी को FIFA का बेस्ट यंग प्लेयर चुना गया

FIFA वर्ल्ड कप के सबसे चमकते सितारों में से एक स्पेन के डिफेंडर पाऊ क्यूबार्सी थे, जिन्हें अरामको कंपनी से FIFA बेस्ट यंग प्लेयर अवॉर्ड मिला।

बहुत छोटा होने के बावजूद, क्यूबार्सी ने डिफेंस में बहुत अच्छी मैच्योरिटी, संतुलन और टैक्टिकल अवेयरनेस दिखाई।

स्पेनिश टीम के डिफेंस में अहम खिलाड़ी थे, क्योंकि टूर्नामेंट के दौरान टीम ने केवल एक गोल खाया था।

यह अवॉर्ड यह साबित करता है कि क्यूबार्सी फुटबॉल में दुनिया के सबसे अच्छे युवा डिफेंडरों में से एक हैं।

नीदरलैंड्स को FIFA गुड बिहेवियर अवार्ड मिला

मैकडोनाल्ड्स द्वारा दिया गया FIFA गुड बिहेवियर अवार्ड नीदरलैंड्स को दिया गया।

जीतने वाली टीम को टूर्नामेंट के दौरान उसके अनुशासन, खेल भावना और दूसरों के प्रति सम्मान के लिए पहचाना जाता है।

यह अवॉर्ड, कॉम्पिटिशन में सफलता के साथ-साथ अच्छे व्यवहार के सिद्धांतों के प्रति FIFA के कमिटमेंट का एक और संकेत है।

FIFA वर्ल्ड कप 2026 अवार्ड्स के विजेताओं की लिस्ट

टीम पुरस्कारों के विजेता

- चैंपियंस: स्पेन
- उपविजेता: अर्जेंटीना
- तीसरा स्थान: इंग्लैंड
- चौथा स्थान: फ्रांस

व्यक्तिगत पुरस्कारों के विजेता

- एडिडास गोल्डन बॉल: रोड्री (स्पेन)
- एडिडास सिल्वर बॉल: लियोनेल मेस्सी (अर्जेंटीना)
- एडिडास ब्रॉन्ज़ बॉल: किलियन एमबाप्पे (फ्रांस)
- एडिडास गोल्डन बूट: किलियन एमबाप्पे (फ्रांस)
- एडिडास सिल्वर बूट: लियोनेल मेस्सी (अर्जेंटीना)
- एडिडास ब्रॉन्ज़ बूट: जूड बेलिंगहम (इंग्लैंड)
- एडिडास गोल्डन ग्लव: उनाई सिमोन (स्पेन)
- FIFA बेस्ट यंग प्लेयर अवॉर्ड: पाउ क्यूबार्सी (स्पेन)
- FIFA फेयर प्ले ट्रॉफी: नीदरलैंड्स।

राष्ट्रीय समाचार

- भारत ने अपनी समृद्ध भाषाई विरासत को बचाने के लिए कोलकाता की नेशनल लाइब्रेरी में देश के पहले इमर्सिव लैंग्वेज म्यूज़ियम , शब्दलोक का उद्घाटन किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया । इस म्यूज़ियम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), ऑगमेंटेड रियलिटी (AR), वर्चुअल रियलिटी (VR), होलोग्राम और इंटरैक्टिव डिस्प्ले का इस्तेमाल किया गया है। यह नौ गैलरी में लगभग 380 भारतीय भाषाओं , अलग-अलग स्क्रिप्ट और साहित्यिक परंपराओं को दिखाता है , जो मौखिक परंपराओं से लिखित साहित्य तक संचार के विकास को दिखाता है। 15 अगस्त, 2026 तक फ्री एंट्री , इसका मकसद भारत की कई भाषाओं वाली और सांस्कृतिक विरासत के साथ लोगों के जुड़ाव को बढ़ावा देना है।
- सुप्रीम कोर्ट (जजों की संख्या) अमेंडमेंट बिल, 2026 , जिसे 20 जुलाई, 2026 को लोकसभा में पेश किया गया था , में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) को छोड़कर सुप्रीम कोर्ट के जजों की मंज़ूर संख्या 33 से बढ़ाकर 37 करने का प्रस्ताव है। एक बार लागू होने के बाद, कोर्ट में कुल 38 जज होंगे। इस कदम का मकसद लगभग 92,385 पेंडिंग केस को सुलझाना, न्यायिक कुशलता में सुधार करना और केस के निपटारे में तेज़ी लाना है। इस अमेंडमेंट के लिए पार्लियामेंट की मंज़ूरी और राष्ट्रपति की मंज़ूरी की ज़रूरत है , क्योंकि यह एक आम कानून है , संविधान में बदलाव नहीं।
- UIDAI का बनाया आधार ऐप 4 करोड़ से ज़्यादा बार डाउनलोड हो चुका है , जो डिजिटल इंडिया सर्विस को तेज़ी से अपनाना दिखाता है। यूज़र एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल ID अपडेट कर सकते हैं , ई-आधार डाउनलोड कर सकते हैं और बायोमेट्रिक लॉक/अनलॉक फ़ीचर मैनेज कर सकते हैं। ऐप ने 11.65 लाख एड्रेस अपडेट , 49 लाख मोबाइल अपडेट , 12.5 लाख ईमेल अपडेट और 1.91 करोड़ बायोमेट्रिक ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड किए हैं। डिजिटल आइडेंटिटी मैनेजमेंट को बढ़ावा देने के लिए, ईमेल अपडेट 31 दिसंबर, 2026 तक फ्री रहेंगे , जिससे सुरक्षित, पेपरलेस और नागरिकों के लिए आसान सरकारी सर्विस मज़बूत होंगी।
- भारत ने देश की पहली सोलर पावर से चलने वाली वॉटर प्यूरिफिकेशन वैन जल - यान लॉन्च की है, जिसे CSIR-CSMCRI ने राइट वॉटर सॉल्यूशंस के साथ मिलकर बनाया है। इसे दूर-दराज और आपदा प्रभावित इलाकों के लिए डिज़ाइन किया गया है। यह रिवर्स ऑस्मोसिस (RO) और अल्ट्राफिल्ट्रेशन (UF) टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नदियों, तालाबों, ग्राउंडवॉटर और स्टोर किए गए सोर्स से पानी को प्यूरिफ़ाई करता है। सोलर पावर से अकेले चलने वाली यह मोबाइल यूनिट बाढ़, साइक्लोन, भूकंप और सूखे के दौरान इमरजेंसी बिजली भी देती है। यह पहल ग्रामीण और मानवीय इलाकों में रिन्यूएबल एनर्जी , क्लाइमेट रेजिलिएंस , पीने का साफ पानी और सस्टेनेबल पब्लिक हेल्थ को सपोर्ट करती है।
- केंद्र सरकार ने अरुणाचल प्रदेश में भारत-चीन बॉर्डर के पास सियोम नदी पर बने 1,000 MW के नाइंग हाइडल प्रोजेक्ट के लिए एनवायरनमेंटल क्लीयरेंस दे दी है । इस रन-ऑफ-द-रिवर हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को एनवायरनमेंटल स्टडी और पब्लिक कंसल्टेशन के बाद एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की एक्सपर्ट अप्रेज़ल कमिटी से मंज़ूरी मिली है। इससे रिन्यूएबल एनर्जी जेनरेशन बढ़ने , एनर्जी सिक्योरिटी बेहतर होने, फॉसिल फ्यूल पर डिपेंडेंस कम होने, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होने , रोज़गार पैदा होने, कनेक्टिविटी बेहतर होने और सियांग और शि-योमी के दूर-दराज के जिलों में सोशियो-इकोनॉमिक डेवलपमेंट में तेज़ी आने की उम्मीद है।
- भारत के सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को रिटायर्ड चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजों के लिए रिटायरमेंट के बाद एक जैसे फायदे देने की सिफारिश करने के लिए दो हफ़्ते के अंदर एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। कमेटी तीन महीने के अंदर सिक्योरिटी, ड्राइवर, घरेलू मदद, मेडिकल रीइंबर्समेंट, टेलीकम्युनिकेशन और रहने की जगह को कवर करते हुए सिफारिशें देगी। कोर्ट ने राज्यों के बीच एक जैसा बर्ताव पर ज़ोर दिया और सवाल किया कि क्या ₹45,000–₹50,000 की मौजूदा फाइनेंशियल मदद काफी है, जबकि केंद्र कमेटी बनाने पर सहमत हो गया।
- खावड़ा सोलर पार्क में अपने पहले 100 MWh वैनेडियम रेडॉक्स फ्लो बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम (VRFB BESS) को मंज़ूरी दी , जो देश का पहला स्वदेशी यूटिलिटी-स्केल नॉन-लिथियम बैटरी प्रोजेक्ट है। NTPC रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड के मालिकाना हक में , बोंडाडा इंजीनियरिंग और डेलेक्ट्रिक सिस्टम्स के साथ , यह प्रोजेक्ट 2027 में पूरा होने वाला है। वैनेडियम-बेस्ड इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल करते हुए , यह टेक्नोलॉजी लंबी लाइफ, बेहतर सुरक्षा और स्केलेबल एनर्जी स्टोरेज देती है, ग्रिड स्टेबिलिटी को मज़बूत करती है, 30 GW खावड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क को सपोर्ट करती है और आत्मनिर्भर भारत और एनर्जी सिक्योरिटी को आगे बढ़ाती है।
- भारत ने 20-22 जुलाई 2026 तक IIT तिरुपति में जियोस्पेशियल टेक्नोलॉजी और इसके एप्लीकेशन पर 5वें BRICS वर्किंग ग्रुप की मेज़बानी की , जिसे डिपार्टमेंट ऑफ़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी (DST) ने ऑर्गनाइज़ किया था। डेलीगेट्स ने GIS, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), रिमोट सेंसिंग, सैटेलाइट इमेजरी, पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT) , और क्लाइमेट रेजिलिएंस पर चर्चा की। मीटिंग का मकसद तिरुपति रिकमेंडेशन (2026) और BRICS एक्शन प्लान (2026–27) बनाना है , जिससे जियोस्पेशियल इनोवेशन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट और इंटरऑपरेबल डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में इंटरनेशनल कोऑपरेशन मज़बूत होगा।
- डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन (DGCA) एविएशन सेफ्टी रिपोर्टिंग को मॉडर्न बनाने के लिए eGCA पोर्टल के साथ इंटीग्रेटेड एक डिजिटल एविएशन इंसिडेंट रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म बना रहा है। यह प्लेटफॉर्म एयरलाइंस, एयरपोर्ट और मेंटेनेंस ऑर्गनाइज़ेशन द्वारा सबमिट की गई मैंडेटरी ऑकरेंस रिपोर्ट (MORs) को डिजिटाइज़ करेगा , और मैनुअल सिस्टम की जगह लेगा। इससे ऑनलाइन रिपोर्टिंग, सेंट्रलाइज़्ड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, तेज़ जांच, कम्प्लायंस मॉनिटरिंग और तेज़ रेगुलेटरी एक्शन मुमकिन होगा। इस पहल से ट्रांसपेरेंसी, डेटा एक्यूरेसी, प्रोएक्टिव रिस्क मैनेजमेंट में सुधार होगा और एविएशन सेफ्टी मज़बूत होगी, क्योंकि भारत का एविएशन सेक्टर लगातार बढ़ रहा है।

- भारत ने आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी एयरोस्पेस क्षमताओं को बढ़ाने के लिए पैनिनियन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा विकसित यंतूर 4.5 kN टर्बोफैन इंजन प्रोग्राम का अनावरण किया। लड़ाकू ड्रोन, क्रूज मिसाइलों और मानव रहित हवाई प्लेटफार्मों के लिए डिज़ाइन किया गया , इंजन में डिजिटल ट्विन-आधारित स्वास्थ्य निगरानी , 12.5 kN तक स्केलेबल थ्रस्ट और उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियां हैं। सबसिस्टम परीक्षण और सत्यापन में प्रवेश करने के बाद, कार्यक्रम में पांच पेटेंट दावे शामिल हैं और उम्मीद है कि यह स्वायत L1 मंच को शक्ति प्रदान करेगा , जिससे आयातित प्रणोदन प्रणालियों पर निर्भरता कम हो जाएगी।
- नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया (NHAI) ने हाईवे पर यात्रा को बेहतर बनाने के लिए राजमार्गयात्रा मोबाइल ऐप पर डिजिटल लोकल पास और मार्गमित्र हेल्प सेंटर लॉन्च किया है । डिजिटल लोकल पास, टोल प्लाज़ा के 20 km के अंदर आने-जाने वाले योग्य यात्रियों को DigiLocker , VAHAN, FASTag और GIS वेरिफिकेशन का इस्तेमाल करके डिजिटल तरीके से महीने का टोल पास पाने में मदद करता है। मार्गमित्र , एक AI-पावर्ड मल्टीलिंगुअल असिस्टेंट है , जो FASTag सपोर्ट, टोल जानकारी, शिकायत का समाधान, शिकायत ट्रैकिंग और सड़क सुरक्षा में मदद देता है, जो भारत के डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव और बेहतर हाईवे मैनेजमेंट में मदद करता है।
- सेंट्रल नो योर कस्टमर (CKYC) एक सेंट्रलाइज़्ड KYC सिस्टम है जिसे CERSAI मैनेज करता है । इससे कस्टमर एक बार आइडेंटिटी वेरिफिकेशन पूरा कर सकते हैं और इसे बैंकों, NBFC, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस कंपनियों में इस्तेमाल कर सकते हैं। वेरिफिकेशन के बाद, यूज़र्स को एक यूनिक 14-डिजिट का CKYC आइडेंटिफिकेशन नंबर (KIN) मिलता है। यह सिस्टम बार-बार होने वाले पेपरवर्क को कम करता है, फाइनेंशियल सर्विसेज़ को तेज़ करता है, ट्रांसपेरेंसी को बेहतर बनाता है और डेटा सिक्योरिटी को मज़बूत करता है। रजिस्ट्रेशन के लिए आधार, पैन, आइडेंटिटी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और फोटो जैसे डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है , जिन्हें ऑथराइज़्ड इंस्टीट्यूशन सेंट्रलाइज़्ड रजिस्ट्री में अपलोड करते हैं।
- कोयला मंत्रालय, जर्मनी की GIZ के साथ एक टेक्निकल कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर साइन करेगा ताकि साइंटिफिक तरीके से खदानों को बंद किया जा सके , पर्यावरण को ठीक किया जा सके और माइनिंग के बाद ज़मीन के सस्टेनेबल इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा सके। इस इवेंट के दौरान, मंत्रालय पहली AAROH (माइन क्लोजर पर सालाना रिपोर्ट) जारी करेगा, जिसमें आज़ादी के बाद से 42 कोयला खदानों को साइंटिफिक तरीके से बंद करने का डॉक्यूमेंट होगा । यह पार्टनरशिप RECLAIM, LIVES और SUVIKALP जैसे प्रोग्राम को मज़बूत करेगी , जिससे इकोसिस्टम को ठीक करने, ज़मीन को फिर से ठीक करने, पानी के मैनेजमेंट और दुनिया के सबसे अच्छे तरीकों से लंबे समय तक चलने वाले कम्युनिटी डेवलपमेंट को बढ़ावा मिलेगा।
- भारत ने कैंपस बायोडायवर्सिटी रजिस्टर (CBR) इनिशिएटिव शुरू किया है , जिसे नेचर कंज़र्वेशन फ़ाउंडेशन (NCF) और नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी (NBA) ने मिलकर लागू किया है । इसका मकसद एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को अपने कैंपस में बायोडायवर्सिटी को डॉक्यूमेंट करने में मदद करना है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी iNaturalist, eBird और SeasonWatch जैसे सिटिज़न साइंस प्लेटफ़ॉर्म का इस्तेमाल करके पौधों, जानवरों, पक्षियों, कीड़ों और दूसरी प्रजातियों को रिकॉर्ड करेंगे। रजिस्ट्रेशन नवंबर 2026 तक खुले रहेंगे , जबकि डॉक्यूमेंटेशन जून 2027 तक जारी रहेगा । इससे स्टूडेंट्स की एक्टिव भागीदारी से कंज़र्वेशन, इकोलॉजिकल रिसर्च, एनवायरनमेंटल अवेयरनेस और मज़बूत बायोडायवर्सिटी-बेस्ड पॉलिसी बनाने को बढ़ावा मिलेगा।
- तमिलनाडु के कुड्डालोर ज़िले का किल्लई गाँव , राज्य का पहला क्लाइमेट-रेज़िलिएंट गाँव बन गया है। यह गाँव साइक्लोन, बाढ़, समुद्र का लेवल बढ़ना, तटीय कटाव और खारे पानी के घुसने से निपटने के लिए कम्युनिटी-बेस्ड स्ट्रेटेजी अपना रहा है। पिचावरम मैंग्रोव फ़ॉरेस्ट के पास मौजूद इस पहल में साइंटिफिक प्लानिंग, मज़बूत इंफ्रास्ट्रक्चर, इकोसिस्टम कंज़र्वेशन, आपदा की तैयारी, वॉटर मैनेजमेंट और सस्टेनेबल रोज़ी-रोटी को मिलाया गया है । मछुआरों, किसानों और लोकल इकोसिस्टम की रक्षा करके, किल्लई दिखाता है कि कैसे कम्युनिटी की भागीदारी और नेचर-बेस्ड सॉल्यूशन लंबे समय तक क्लाइमेट रेजिलिएंस बना सकते हैं और दूसरे तटीय इलाकों के लिए एक मॉडल बन सकते हैं।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 22 जुलाई 2026 को नॉर्थ मैसेडोनिया के स्कोप्जे शहर के म्यूज़ियम में राष्ट्रपति गोर्दाना सिलजानोव्स्का- दावकोवा की मौजूदगी में महात्मा गांधी की एक मूर्ति का अनावरण किया । समारोह के दौरान, उन्होंने गांधी के सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों को न्याय, शांति, आज़ादी और बातचीत को बढ़ावा देने वाले यूनिवर्सल मूल्यों के तौर पर बताया। यह स्मारक बढ़ती भारत-नॉर्थ मैसेडोनिया दोस्ती , कल्चरल डिप्लोमेसी और आज की ग्लोबल चुनौतियों के बीच सहनशीलता, आपसी सम्मान और शांतिपूर्ण साथ रहने के लिए एक साझा कमिटमेंट का प्रतीक है ।
- 30 जून 2026 तक भारत की इंस्टॉल्ड विंड पावर कैपेसिटी 57,443 MW तक पहुंच गई , जिसमें FY 2025–26 के दौरान 6,057 MW और जुड़ेंगे , जो पिछले तीन सालों में सबसे ज़्यादा सालाना बढ़ोतरी है। मिनिस्ट्री ऑफ़ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी (MNRE) के मुताबिक , विंड एनर्जी जेनरेशन बढ़कर 106 बिलियन यूनिट हो गया , जबकि गुजरात 16,086 MW कैपेसिटी के साथ लीडिंग स्टेट बना रहा । ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल (GWEC) द्वारा दुनिया भर में चौथे नंबर पर , भारत ट्रांसमिशन रिफॉर्म, ऑफशोर विंड पॉलिसी और इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव के ज़रिए रिन्यूएबल एनर्जी को बढ़ाना जारी रखे हुए है।
- भारत ने अपने ब्रॉड गेज रेलवे नेटवर्क का 99.6% इलेक्ट्रिफिकेशन पूरा कर लिया है , जिससे इंडियन रेलवे स्विट्ज़रलैंड के बाद दुनिया का दूसरा सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफाइड रेलवे सिस्टम बन गया है। 2014 से , 48,000 से ज़्यादा रूट किलोमीटर को इलेक्ट्रिफाइड किया गया है, जिससे डीज़ल की खपत 2015-16 में 293 करोड़ लीटर से घटकर 2024-25 में 108 करोड़ लीटर हो गई है । रेल ट्रांसपोर्ट, रोड ट्रांसपोर्ट की तुलना में प्रति टन-किलोमीटर लगभग 89% कम CO_2 एमिट करता है , जबकि 1,260 MW से ज़्यादा सोलर और विंड कैपेसिटी इंस्टॉल की गई है, जो भारत के क्लाइमेट और एनर्जी लक्ष्यों को सपोर्ट करती है।

- न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के तहत 2033 तक लगभग $2 बिलियन के इन्वेस्टमेंट से कम से कम पांच स्वदेशी छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर (SMR) बनाएगा। BARC के डिज़ाइन किए गए इस प्रोग्राम में क्लीन एनर्जी को बढ़ावा देने, हाइड्रोजन प्रोडक्शन को सपोर्ट करने और एनर्जी सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए भारत SMR, SMR-55 और HTGR टेक्नोलॉजी शामिल हैं। मॉड्यूलर रिएक्टर बेहतर सेफ्टी, तेज़ी से डिप्लॉयमेंट और कम लागत देते हैं, जबकि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को बढ़ावा देने वाले पॉलिसी रिफॉर्म इनोवेशन को तेज़ करेंगे। यह पहल 2031-32 तक 22 GW न्यूक्लियर कैपेसिटी और 2047 तक 100 GW के भारत के टारगेट को सपोर्ट करती है , जो कार्बन एमिशन में कमी और सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ में अहम योगदान देगी।
- केंद्र सरकार एग्जाम पेपर लीक को रोकने के लिए एक नया कानून लाने की योजना बना रही है , जिसमें फास्ट-ट्रैक कोर्ट और दोषियों के लिए सख्त सज़ा का प्रावधान होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित यह कानून कई हाई-प्रोफाइल पेपर लीक मामलों के बाद आया है, जिनसे हजारों उम्मीदवार प्रभावित हुए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की विश्वसनीयता कम हुई। प्रस्तावित बिल को संसद में पेश करने से पहले केंद्रीय कैबिनेट द्वारा रिव्यू किया जाएगा। इसका मकसद जल्दी न्याय सुनिश्चित करना , ऑर्गनाइज्ड एग्जाम फ्रॉड नेटवर्क को खत्म करना, असली उम्मीदवारों की सुरक्षा करना, ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी में सुधार करना , और भारत के रिक्रूटमेंट और एडमिशन एग्जाम सिस्टम में लोगों का भरोसा वापस लाना है।
- " सहकार से समृद्धि" के विज़न के तहत नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोऑपरेटिव-बेस्ड राइड सर्विस , भारत टैक्सी लॉन्च की। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल ने इसका उद्घाटन किया । यह प्लेटफॉर्म ड्राइवरों को कमीशन-बेस्ड पार्टनर के बजाय कोऑपरेटिव मालिक (सारथी) मानता है। यह सर्विस फिक्स्ड किराया, कोई सर्ज प्राइसिंग नहीं, ट्रांसपेरेंट चार्ज और बेहतर पैसेंजर सेफ्टी देती है, जिससे ड्राइवरों की पक्की कमाई पक्की होती है। दिल्ली और गुजरात में सफल लागू होने के बाद , यह पहल पूरे महाराष्ट्र में फैलेगी, जिससे राज्य का कोऑपरेटिव मूवमेंट मजबूत होगा और सस्ता और भरोसेमंद ट्रांसपोर्टेशन मिलेगा।
- भारत ने गंगा नदी पर साफ़ और टिकाऊ नदी ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 23 जुलाई 2026 को वाराणसी के नमो घाट पर इलेक्ट्रिक बोट कन्वर्ज़न पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। VDA और GAIL द्वारा लागू किया गया यह प्रोजेक्ट फ्यूल से चलने वाली नावों को 15 kW मोटर, लिथियम बैटरी, GPS ट्रैकिंग, EV चार्जिंग और रिमोट मॉनिटरिंग से लैस इलेक्ट्रिक नावों में बदलता है । शुरुआत में, 20 नावों को बदला जाएगा, जिससे प्रदूषण कम होगा, इको-टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा और ग्रीन मोबिलिटी को सपोर्ट मिलेगा , साथ ही नाविकों को पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी अपनाने के लिए बढ़ावा मिलेगा।
- वीव्स ऑफ़ इंडिया फ़ेस्टिवल 2026 , जो 24 जुलाई से 7 अगस्त तक CCIE, नई दिल्ली में होगा , मिनिस्ट्री ऑफ़ टेक्सटाइल्स के तहत 116 पारंपरिक हैंडलूम बुनाई को दिखाएगा। बनारसी सिल्क, जामदानी, कांचीपुरम सिल्क और संबलपुरी इकत की खासियत वाला यह इवेंट भारत की टेक्सटाइल विरासत को बढ़ावा देता है , कारीगरों को सपोर्ट करता है, गांव में रोज़गार बढ़ाता है और देसी हैंडलूम प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल को बढ़ावा देता है। यह आने वाले 12वें नेशनल हैंडलूम डे (7 अगस्त) को भी मनाता है, जो 1905 के स्वदेशी आंदोलन की याद में मनाया जाता है।
- मिशन सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 एकीकृत आंगनवाड़ी सर्विस, पोषण अभियान, और किशोरियों के लिए स्कीम ताकि न्यूट्रिशन, बचपन की देखभाल और महिलाओं की हेल्थ बेहतर हो सके। FY 2025–26 के लिए ₹21,960 करोड़ के एलोकेशन के साथ , यह मिशन आंगनवाड़ी सेंटर्स को मॉडर्नाइज़ करता है और डिजिटल गवर्नेंस को मज़बूत करता है। 10 लाख से ज़्यादा आंगनवाड़ी वर्कर्स को पोषण भी पढ़ाई भी के तहत ट्रेनिंग दी गई है , जबकि ICT-बेस्ड सिस्टम रियल-टाइम ग्रोथ मॉनिटरिंग और बेहतर पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को मुमकिन बनाते हैं।
- यूनियन कैबिनेट ने एग्जाम पेपर लीक और ऑर्गनाइज़्ड चीटिंग को रोकने के लिए पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ़ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 में बदलाव को मंज़ूरी दी है। इस प्रपोज़ल में कम से कम जेल की सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 5 साल और ज़्यादा से ज़्यादा जुर्माना ₹ 10 करोड़ कर दिया गया है। इसमें पेपर लीक, किसी और की जगह किसी और की पहचान, नकली वेबसाइट और ऑर्गनाइज़्ड फ्रॉड जैसे अपराधों से निपटने के लिए फास्ट-ट्रैक कोर्ट और स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सिस्टम भी शामिल हैं , ताकि फेयर और ट्रांसपेरेंट एग्जाम हो सकें।
- विरोध करने का अधिकार संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) और 19(1)(b) के तहत सुरक्षित है , जो शांति से बात करने और इकट्ठा होने की इजाज़त देता है। हालाँकि, यह पब्लिक ऑर्डर, नेशनल सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी से जुड़ी ज़रूरी पाबंदियों के तहत आता है। कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध के बाद , विरोध के नियमों पर फिर से बहस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों ने पक्का किया है कि प्रदर्शन शांतिपूर्ण रहने चाहिए और उनसे अनिश्चित समय के लिए पब्लिक जगहों को ब्लॉक नहीं करना चाहिए या पब्लिक लाइफ में रुकावट नहीं डालनी चाहिए।
- इंडियन रेलवे ने AC कोच के बेडरोल में हाइजीन को बेहतर बनाने के लिए पुणे, जयपुर और जोधपुर में मैकेनाइज्ड लॉन्ड्री में AI-बेस्ड लिनन स्टेन डिटेक्शन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया। यह सिस्टम ऑटोमेटेड स्टेन डिटेक्शन के लिए कंप्यूटर विज़न, मशीन लर्निंग, इमेज एनालिसिस और हाई-रिज़ॉल्यूशन कैमरों का इस्तेमाल करता है। यह व्हिटो -मीटर्स, CCTV सर्विलांस और मैनुअल इंस्पेक्शन जैसे मौजूदा क्वालिटी चेक को कॉम्प्लिमेंट करता है , जिसका मकसद पैसेंजर सैटिस्फैक्शन को बेहतर बनाना और स्मार्ट रेलवे मॉडर्नाइजेशन को सपोर्ट करना है।
- जून 2026 में राज्यसभा का टर्म खत्म होने के बाद , रेलवे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ के केंद्रीय राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने इस्तीफ़ा दे दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 75(2) के तहत इस्तीफ़ा स्वीकार कर लिया। बिट्टू ने कहा कि वह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की राजनीति पर ध्यान देना चाहते हैं । पहले कांग्रेस के नेता रहे बिट्टू 2024 में BJP में शामिल हुए और पहले लोकसभा में लुधियाना और आनंदपुर साहिब का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं।

- इंडियन साइबरक्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) ने GitHub को जैक डोर्सी के बनाए ब्लूटूथ -बेस्ड डीसेंट्रलाइज़्ड मैसेजिंग ऐप बिटचैट से जुड़ी रिपॉजिटरी हटाने का निर्देश दिया । सरकार ने IT एक्ट, 2000 के सेक्शन 79(3)(b) और IT रूल्स, 2021 का इस्तेमाल करते हुए नेशनल सिक्योरिटी, साइबरक्राइम, गलत जानकारी और एनॉनिमस कम्युनिकेशन पर चिंता जताई। सिक्योरिटी की कमज़ोरियों की पहले की रिपोर्ट्स ने भी प्लेटफॉर्म की सेफ्टी और गलत इस्तेमाल को लेकर चिंता जताई थी।
- भारत के सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि कोर्ट की कार्यवाही के वीडियो को बिना किसी अधिकारी की पहले से मंज़ूरी के ऑनलाइन अपलोड, शेयर या सर्कुलेट नहीं किया जा सकता । इस आदेश का मकसद गुमराह करने वाले एडिट, AI से बनी गलत जानकारी और सनसनीखेज कंटेंट को रोकना है , जिससे न्यायपालिका में लोगों का भरोसा कम हो सकता है। कोर्ट ने वकीलों द्वारा प्रमोशन के लिए कोर्टरूम क्लिप का इस्तेमाल करने पर बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया की राय भी मांगी और चेतावनी दी कि लगातार गलत इस्तेमाल से लाइव-स्ट्रीमिंग एक्सेस पर रोक लग सकती है।

राज्य समाचार

- अमूल ने हावड़ा फ़ूड पार्क में अपना ₹700 करोड़ का बंगाल डेयरी प्रोजेक्ट लॉन्च किया , जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा दही बनाने का प्लांट है। यह फ़ैसिलिटी रोज़ाना 30 लाख लीटर दूध प्रोसेस करेगी और 10 लाख kg दही , पैकेज्ड दूध, UHT दूध , आइसक्रीम, पनीर, घी, मिठाई और फ़्लेवर्ड दूध बनाएगी। पहले फ़ेज़ में कोऑपरेटिव प्रोक्योरमेंट और बेहतर इनकम के मौकों से लगभग 1.2 लाख डेयरी किसानों को फ़ायदा होगा। व्हाइट रेवोल्यूशन 2.0 को सपोर्ट करते हुए , इस प्रोजेक्ट में ब्रीड इम्प्रूवमेंट प्रोग्राम और किसान वेलफ़ेयर इनिशिएटिव भी शामिल हैं।
- APEDA ने सिंगापुर को कश्मीरी चेरी और प्लम का पहला एक्सपोर्ट किया , जो भारत के हॉर्टिकल्चर एक्सपोर्ट के लिए एक मील का पत्थर है। इस शिपमेंट में शोपियां और पुलवामा ज़िलों से अरेको चेरी और सेंट्रोस प्लम शामिल थे। ओसम फ़ूड सॉल्यूशंस LLP और फ्रूट मास्टर एग्रो फ्रेश प्राइवेट लिमिटेड के सपोर्ट से, इन प्रोडक्ट्स की साइंटिफिक हार्वेस्टिंग, ग्रेडिंग, हाइजीनिक पैकेजिंग, कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स और फाइटोसैनिटरी चेकिंग की गई। इस पहल से किसानों की कमाई 50% से ज़्यादा बढ़ने की उम्मीद है, साथ ही सिंगापुर, अबू धाबी और दुबई जैसे मार्केट में एक्सपोर्ट बढ़ने की भी उम्मीद है।
- महाराष्ट्र ने ₹45 करोड़ के निवेश के साथ ठाणे क्रीक फ्लेमिंगो सैंक्चुअरी में भारत की पहली AI-पावर्ड बर्ड सैंक्चुअरी को मंज़ूरी दी है । यह प्रोजेक्ट एक AI-बेस्ड बर्ड डिटेक्शन और मॉनिटरिंग सेंटर बनाएगा जो पक्षियों की प्रजातियों की पहचान करने, माइग्रेशन को ट्रैक करने और रियल टाइम में इकोलॉजिकल डेटा इकट्ठा करने में सक्षम होगा। दूसरे आकर्षणों में बर्डवॉचिंग टावर, नेचर ट्रेल्स, इंटरैक्टिव एग्ज़िबिट और एजुकेशनल सुविधाएँ शामिल हैं। यह पहल मुंबई और नवी मुंबई के पास साइंटिफिक बायोडायवर्सिटी मॉनिटरिंग और सस्टेनेबल इको-टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए वाइल्डलाइफ़ कंज़र्वेशन के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जोड़ती है।
- मध्य प्रदेश कैबिनेट ने यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड (UCC) बिल, 2026 को मंज़ूरी दे दी है। उत्तराखंड, गुजरात और असम के बाद मध्य प्रदेश ऐसा कानून लाने वाला चौथा भारतीय राज्य बन गया है । संविधान के आर्टिकल 44 के आधार पर , यह बिल शादी, तलाक़, विरासत, गोद लेने, गुज़ारे का खर्च और लिव-इन रिलेशनशिप को कंट्रोल करने वाले आम सिविल कानूनों का प्रस्ताव करता है। यह शादी का रजिस्ट्रेशन, विरासत के बराबर अधिकार और एक ही शादी को ज़रूरी बनाता है, जबकि एक से ज़्यादा शादी, तीन तलाक़ और निकाह हलाला पर रोक लगाता है । पारंपरिक परंपराओं को बनाए रखने के लिए अनुसूचित जनजातियों और खास तौर पर कमज़ोर आदिवासी समूहों (PVTGs) को छूट दी गई है।
- भारत सरकार और मेघालय ने GI-टैग वाली लाकाडोंग हल्दी की वैल्यू चेन को मज़बूत करने के लिए ₹175.45 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करते हुए मिशन गोल्डन स्पाइस लॉन्च किया है। पांच साल के इस प्रोजेक्ट का मकसद 2030 तक खेती को 2,500 हेक्टेयर से बढ़ाकर 7,000 हेक्टेयर करना है, जिससे 17,500 से ज़्यादा किसानों , खासकर महिलाओं को फ़ायदा होगा । 7-12% करक्यूमिन कंटेंट के लिए जानी जाने वाली लाकाडोंग हल्दी को बेहतर प्रोसेसिंग, ब्रांडिंग और एक्सपोर्ट सपोर्ट मिलेगा। इस मिशन का टारगेट ₹100 करोड़ की हल्दी इकॉनमी बनाना है , साथ ही US, यूरोप, जापान और खाड़ी देशों जैसे मार्केट में एक्सपोर्ट बढ़ाना है।
- छत्तीसगढ़ सरकार ने अग्निवीर सैनिकों के लिए क्लास-III सिविल सर्विस में खाली जगहों के लिए छत्तीसगढ़ रिज़र्वेशन रूल्स, 2026 के तहत चुनी हुई क्लास-III सरकारी नौकरियों में अग्निवीरों के लिए 10% रिज़र्वेशन को मंज़ूरी दी है। पुलिस कांस्टेबल, फ़ॉरेस्ट गार्ड और जेल वार्डर जैसे पदों को कवर करते हुए , यह पॉलिसी अग्निपथ स्कीम के तहत चार साल की सर्विस पूरी करने के बाद अग्निवीरों को सपोर्ट करती है । योग्य उम्मीदवारों के पास एक वैलिड डिस्चार्ज सर्टिफ़िकेट और छत्तीसगढ़ का डोमिसाइल होना चाहिए, जिससे उन्हें सिविलियन पब्लिक सर्विस में जाने में आसानी हो।
- आंध्र प्रदेश ने हाइपरलेजर फैब्रिक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके ज़मीन के रिकॉर्ड को मॉडर्न बनाने के लिए मी भूमि-ब्लॉकचेन पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया । नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर (NIC) का बनाया यह सिस्टम सात मंडलों और 89 री-सर्वे गांवों में रेवेन्यू, सर्वे और रजिस्ट्रेशन रिकॉर्ड को जोड़ता है । यह ऑटो-म्यूटेशन, ज़मीन का सबडिवीजन, हद में सुधार और सुरक्षित डिजिटल वेरिफिकेशन को मुमकिन बनाता है , जिससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, छेड़छाड़ रुकती है, ज़मीन के झगड़े कम होते हैं और सरकारी डिपार्टमेंट, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए तेज़ सर्विस मिलती हैं।
- झारखंड ने रांची में राज्य का पहला झारखंड फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (JFTI) बनाने के लिए सत्यजीत रे फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट (SRFTI) के साथ एक MoU साइन किया है। झारखंड फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (JFDCL) का बनाया यह इंस्टीट्यूट शुरू में सिनेमैटोग्राफी, डायरेक्शन, एडिटिंग, एनिमेशन, साउंड डिजाइन, स्क्रीनप्ले राइटिंग और प्रोडक्शन में सर्टिफिकेट कोर्स ऑफर करेगा , और बाद में अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम भी शुरू करने का प्लान है। इस पहल का मकसद रीजनल स्टोरीटेलिंग को मजबूत करना, कल्चरल हेरिटेज को बचाना और राज्य की बढ़ती फिल्म, OTT और डिजिटल मीडिया इंडस्ट्री को सपोर्ट करना है।

- राजस्थान ने मुख्यमंत्री युवा सुयोग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है । यह युवाओं में स्पोर्ट्स, रोज़गार, स्किल डेवलपमेंट, लीडरशिप और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने वाली एक डिजिटल पहल है । बगरू विधानसभा क्षेत्र और बारां जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट के साथ शुरू हुआ यह प्लेटफॉर्म युवा सुयोग पोर्टल के ज़रिए रजिस्ट्रेशन कराता है , स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन आयोजित करता है, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मैप करता है और ज़िला-लेवल युवा सुयोग क्लब बनाता है। MY भारत प्रोग्राम के साथ जुड़ने से वॉलंटियरिंग, सिविक पार्टिसिपेशन और सरकारी मदद के ज़रिए देश भर में युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा मिलता है।
- पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड (PSEB) की सरबत.AI पहल के तहत क्लास 1 से क्लास 12 तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को मेनस्ट्रीम सब्जेक्ट के तौर पर शुरू करने वाला पंजाब पहला भारतीय राज्य बन गया है। AI को शुरू में लाइव क्लास, प्रोजेक्ट, असेसमेंट और डिजिटल लर्निंग टूल्स का इस्तेमाल करके क्लास VIII-XII के कंप्यूटर साइंस करिकुलम में शामिल किया जाएगा। 12,000 से ज़्यादा कंप्यूटर साइंस टीचरों को नीव AI, गूगल, इंटेल, कैनवा और FA-AI की मदद से खास ट्रेनिंग मिलेगी , जिससे स्टूडेंट्स भविष्य में AI से चलने वाले करियर के लिए तैयार होंगे।
- उत्तराखंड और मध्य प्रदेश के बाद हिमाचल प्रदेश तीसरा भारतीय राज्य बन गया है , जिसने दवा और वैज्ञानिक मकसद के लिए रेगुलेटेड कैनेबिस की खेती की इजाज़त दी है। NDPS अमेंडमेंट रूल्स, 2026 के तहत , खेती की इजाज़त सिर्फ़ सुरक्षित ग्रीनहाउस या पॉलीहाउस में दी जाती है, जिसमें जियो-टैगिंग, CCTV सर्विलांस, सर्टिफाइड बीज और डिटेल्ड रिकॉर्ड-कीपिंग के ज़रिए कड़ी निगरानी होती है । मनोरंजन के लिए इस्तेमाल पर रोक रहेगी, जबकि बनाने वालों को लाइसेंस लेना होगा और कम से कम ₹100 करोड़ का निवेश करना होगा । इस पॉलिसी का मकसद फार्मास्युटिकल रिसर्च, मेडिकल इनोवेशन, निवेश और कैनेबिस-बेस्ड प्रोडक्ट डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है , साथ ही गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए सरकार की सख्त निगरानी भी पक्की करना है।
- राजस्थान ने पानी की सुरक्षा, ग्राउंडवाटर कंजर्वेशन, सिंचाई और सस्टेनेबल वॉटर मैनेजमेंट को मजबूत करने के लिए स्टेट वॉटर प्लान 2047 लॉन्च किया । यह प्लान जल जीवन मिशन, AMRUT 2.0 और अटल भूजल योजना को जोड़ता है, साथ ही रिवर-लिंकिंग, रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, डिजिटल मॉनिटरिंग और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देता है । बड़ी पहलों में रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट , यमुना वॉटर एग्रीमेंट और देवास III और IV प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ AMRUT 2.0 के तहत ₹5,100 करोड़ शामिल हैं ।
- HCL टेक्नोलॉजीज़ , सर्वम AI और ओडिशा सरकार के साथ पार्टनरशिप में , ₹15,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से भुवनेश्वर में अपना पहला AI-ऑप्टिमाइज़्ड डेटा सेंटर और ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर बनाएगी । ओडिशा सॉवरेन AI पार्क में मौजूद इस प्रोजेक्ट से 2028 तक 5,000 डायरेक्ट जॉब्स मिलने की उम्मीद है और यह AI रिसर्च, क्लाउड कंप्यूटिंग, मॉडल ट्रेनिंग और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करेगा, जिससे भारत का सॉवरेन AI इकोसिस्टम मज़बूत होगा ।

अंतरराष्ट्रीय समाचार

- एंडी बर्नहैम 20 जुलाई 2026 को यूनाइटेड किंगडम के नए प्रधानमंत्री बने। उन्हें किंग चार्ल्स III ने कीर स्टारमर के इस्तीफे के बाद नियुक्त किया था। ग्रेटर मैनचेस्टर के पहले मेयर रहे बर्नहैम ने पार्लियामेंट्री कॉन्फिडेंस हासिल किया और उन्हें UK के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रैक्टिस के तहत सरकार बनाने के लिए बुलाया गया। 10 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर अपने पहले भाषण में , उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को " सर्किट ब्रेकर " सरकार बताया और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस और पब्लिक ट्रस्ट को वापस लाने के लिए लॉन्ग-टर्म रिफॉर्म्स का वादा किया ।
- प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने चिसीनाउ में प्रेसिडेंट माइया सैंडू के साथ बातचीत करते हुए, किसी भारतीय प्रेसिडेंट का मोल्दोवा का पहला स्टेट विज़िट शुरू किया । दोनों नेताओं ने ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, एग्रीकल्चर, हेल्थकेयर, रिन्यूएबल एनर्जी, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनोवेशन और एजुकेशन में कोऑपरेशन पर चर्चा की। भारत ने ITEC ट्रेनिंग स्लॉट बढ़ाने , स्पेशलाइज़्ड AI और साइबर डिप्लोमेसी कोर्स शुरू करने की घोषणा की, और मोल्दोवा को कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI) और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (GBA) में शामिल होने के लिए इनवाइट किया , जिससे बाइलेटरल रिश्ते मज़बूत होंगे।
- भारत, फिशरीज़ सब्सिडी पर एग्रीमेंट को स्वीकार करने वाला 123वां WTO सदस्य बन गया है , जिससे सस्टेनेबल फिशरीज़ और समुद्री संरक्षण के लिए उसका कमिटमेंट और मज़बूत हुआ है। यह एग्रीमेंट, जिसे MC12 (2022) में अपनाया गया था और जो 15 सितंबर 2025 से लागू होगा , गैर-कानूनी, बिना रिपोर्ट की और बिना रेगुलेटेड (IUU) फिशिंग , ज़्यादा फिशिंग और मछली के घटते स्टॉक को सपोर्ट करने वाली सब्सिडी पर रोक लगाता है । यह सिर्फ़ समुद्री जंगली कैप्चर फिशरीज़ पर लागू होता है , जिससे एक्वाकल्चर और इनलैंड फिशरीज़ पर कोई असर नहीं पड़ता। यह कदम PMMSY और भारत की फिशरीज़ पॉलिसी के साथ मेल खाता है, साथ ही पारंपरिक मछुआरों की रक्षा भी करता है।
- खलील अल-हया को हमास का नया ओवरऑल लीडर चुना गया , जो याह्या सिनवार की जगह लेंगे , जो अक्टूबर 2024 में गाजा संघर्ष के दौरान मारे गए थे। हमास के एक सीनियर लीडर और मिस्र और कतर की मध्यस्थता से हुई इनडायरेक्ट सीज़फ़ायर बातचीत में मुख्य वार्ताकार , अल-हया ने 69 सदस्यों वाले इलेक्टोरल कॉलेज के ज़रिए दूसरे राउंड के रनऑफ़ में खालिद मेशाल को हराया । उन्होंने मिलिट्री नाकामियों, इंटरनेशनल जांच और चल रही सीज़फ़ायर बातचीत के बीच लीडरशिप संभाली है, और उम्मीद है कि हमास की भविष्य की स्ट्रैटेजी में डिप्लोमेसी सेंट्रल रहेगी।
- फ्रांस ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करने से रोकने वाले एक अहम कानून को मंज़ूरी दी है । इस तरह, वह पूरे देश में ऐसी रोक लगाने वाला पहला यूरोपियन देश बन गया है । प्रेसिडेंट इमैनुएल मैक्रों के सपोर्ट से, यह कानून सितंबर 2026 से उम्र का वेरिफिकेशन ज़रूरी कर देगा , जबकि पूरा बैन जनवरी 2027 से लागू होगा। इस कानून का मकसद बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी को बेहतर बनाना , मेंटल हेल्थ की रक्षा करना, साइबरबुलिंग को कम करना और नुकसानदायक कंटेंट के संपर्क को कम करना है, हालांकि प्राइवेसी, डेटा प्रोटेक्शन और इसे लागू करने को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं ।

Test Prime By Adda247

ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION

Test. Analyze. Improve. Repeat.

Don't just prepare. Perform.

Test Prime – built only for mock tests.

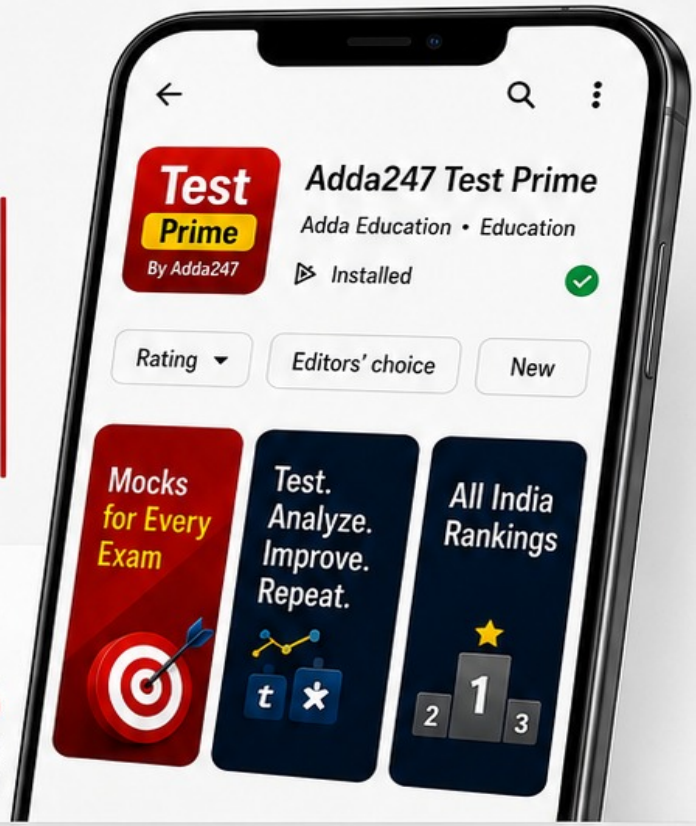

1,50,000+ Mock Tests

25,000+ Previous Year Papers

800+ Exam Covered

500% Refund on Selection

5 lakh+ Free Quizzes

Daily Free PDFs

Top Alerts Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- Multilingual
- Detailed Solution
- Strong and Weak Areas
- All India Rankings

- Safe & Reliable
- Trusted by Lakhs of Aspirants
- Your Success, Our Mission

DOWNLOAD TEST PRIME

Your Success Partner!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store

- भारतीय मूल के ब्रिटिश पॉलिटिशियन कनिष्क नारायण को यूनाइटेड किंगडम का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिनिस्टर बनाया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में जन्मे और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े कनिष्क नारायण UK की AI स्ट्रेटेजी को लीड करेंगे, जिसमें AI सेफ्टी, इनोवेशन, रेगुलेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, रिसर्च, स्टार्टअप्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और एथिकल गवर्नेंस शामिल हैं। उनका अपॉइंटमेंट गवर्नेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती इंपॉर्टेंस को दिखाता है, साथ ही भारतीय मूल के प्रोफेशनल्स की बढ़ती ग्लोबल लीडरशिप को भी हाईलाइट करता है।
- प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नॉर्थ मैसेडोनिया का बाइलेटरल दौरा करने वाली पहली इंडियन प्रेसिडेंट बनीं , जिससे 1995 में बने रिश्ते और मज़बूत हुए । दोनों देश ट्रेड, टेक्नोलॉजी, हेल्थकेयर, टूरिज्म, एग्रीकल्चर, AI, फार्मास्यूटिकल्स, बायोटेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल और स्किल डेवलपमेंट में कोऑपरेशन को और गहरा करने पर सहमत हुए। इंडिया ने ITEC ट्रेनिंग को बढ़ाने , हेल्थकेयर MoU को पांच साल के लिए रिन्यू करने और बाइलेटरल रिश्तों को बढ़ाने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस (ISA), कोएलिशन फॉर डिजास्टर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर (CDRI), और ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस (GBA) के ज़रिए कोऑपरेशन को बढ़ावा देने का ऐलान किया।
- भारत ने BRICS नेटवर्क यूनिवर्सिटी (BRICS NU) गवर्निंग बोर्ड मीटिंग और अपनी BRICS प्रेसीडेंसी 2026 के तहत ट्रेडिशनल और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम पर पहली कॉन्फ्रेंस होस्ट की । शिक्षा मंत्रालय द्वारा आयोजित इस इवेंट में हायर एजुकेशन, रिसर्च कोलेबोरेशन, फैकल्टी एक्सचेंज, इनोवेशन, एथिकल AI और इंडिजिनस नॉलेज के संरक्षण पर फोकस किया गया। भारत ने ट्रेडिशनल और इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम पर एक नया इंटरनेशनल थीमैटिक ग्रुप बनाने का प्रस्ताव रखा , जिसे एकेडमिक कोऑपरेशन को मजबूत करने के लिए BRICS सदस्य देशों से बड़ा सपोर्ट मिला।
- सस्टेनेबल सिटीज़ एंड सोसाइटी में छपी ऑक्सफ़ोर्ड यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में दिल्ली, मुंबई और चेन्नई को दुनिया के टॉप 10 शहरों में शामिल किया गया है , जो बहुत ज़्यादा गर्मी के लिए सबसे ज़्यादा असुरक्षित हैं। दुनिया के 205 शहरों का आकलन करते हुए , रिसर्च में तापमान के संपर्क, आबादी की कमज़ोरी और ढलने की क्षमता का मूल्यांकन किया गया। दिल्ली दूसरे स्थान पर रही , जबकि मुंबई और चेन्नई क्रमशः छठे और नौवें स्थान पर रहे । स्टडी में बढ़ते क्लाइमेट से जुड़े जोखिमों से निपटने के लिए ग्रीन स्पेस, क्लाइमेट-रेज़िलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थकेयर सिस्टम, अर्बन प्लानिंग और हीट एक्शन प्लान को बढ़ाने की सलाह दी गई है।
- यूनाइटेड स्टेट्स ने US एटॉमिक एनर्जी एक्ट, 1954 के सेक्शन 123 के तहत सऊदी अरब के साथ 30 साल के सिविलियन न्यूक्लियर कोऑपरेशन एग्रीमेंट को मंज़ूरी दी । यह एग्रीमेंट रिएक्टर डेवलपमेंट, न्यूक्लियर फ्यूल सप्लाई, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ में कोऑपरेशन को सपोर्ट करता है , जिससे सऊदी अरब के एनर्जी डायवर्सिफिकेशन में मदद मिलेगी। हालांकि, इस डील में यूरेनियम एनरिचमेंट और खर्च किए गए फ्यूल रीप्रोसेसिंग पर गोल्ड स्टैंडर्ड पाबंदियां शामिल नहीं हैं , जिससे न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन रिस्क पर बहस छिड़ गई है , जबकि सपोर्टर्स इसे एक अहम स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के तौर पर देख रहे हैं।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के बुखारेस्ट दौरे के दौरान भारत और रोमानिया ने साइंस, टेक्नोलॉजी और स्पोर्ट्स में सहयोग को मज़बूत करने के लिए कई MoU पर साइन किए। राष्ट्रपति निकुसोर डैन के साथ बातचीत में ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, डिफेंस , IT, रिन्यूएबल एनर्जी, एजुकेशन और इनोवेशन पर भी बात हुई। राष्ट्रपति मुर्मू का कोट्रोसेनी पैलेस में औपचारिक स्वागत हुआ और उन्होंने इंडिया-रोमानिया बिज़नेस फोरम और इंडियन डायस्पोरा के साथ बातचीत में हिस्सा लिया। इन समझौतों से दोनों देशों के रिश्ते और गहरे होने, आर्थिक सहयोग बढ़ने और रोमानिया और यूरोपियन यूनियन के साथ भारत के जुड़ाव और मज़बूत होने की उम्मीद है।
- भारत ने केन्या को 4.5 टन मेडिकल मदद दी ताकि देश की इबोला से निपटने की तैयारी और बीमारी से निपटने की क्षमता बढ़ सके। नैरोबी में हाई कमिश्नर आदर्श स्वैका ने यह मदद दी , जिसमें PPE किट, सैंपल ट्रांसपोर्ट किट, इंफ्रारेड थर्मामीटर, फेस शील्ड और प्रोटेक्टिव बूट शामिल थे। यह सप्लाई हेल्थकेयर वर्कर, बीमारी की निगरानी, लैब टेस्टिंग और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सिस्टम को सपोर्ट करेगी । यह पहल ग्लोबल हेल्थ कोऑपरेशन, मानवीय मदद और केन्या और अफ्रीकी देशों के साथ हेल्थकेयर में लंबे समय से चली आ रही पार्टनरशिप के लिए भारत के कमिटमेंट को दिखाती है।
- अपनी BRICS चेयरशिप 2026 के तहत चंडीगढ़ में 16वीं BRICS हेल्थ मिनिस्टर्स मीटिंग होस्ट की , जिसमें 11 सदस्य देशों के रिप्रेजेंटेटिव शामिल हुए । मीटिंग में महामारी की तैयारी, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, डिजिटल हेल्थ, AI, टेलीमेडिसिन और सभी तक हेल्थकेयर की पहुंच पर फोकस किया गया । सदस्यों ने 16वें हेल्थ मिनिस्टीरियल डिक्लेरेशन को अपनाया, जिसमें मजबूत हेल्थकेयर सिस्टम को मजबूत करने के लिए सहयोग की पुष्टि की गई। भारत ने NIMHANS बेंगलुरु द्वारा कोऑर्डिनेट किए जाने वाले मेंटल वेलनेस पर सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस का एक BRICS नेटवर्क बनाने का प्रस्ताव रखा , साथ ही पारंपरिक मेडिसिन, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड और सुरक्षित हेल्थ डेटा एक्सचेंज में सहयोग का भी समर्थन किया।
- स्पेन अपने अब तक के सबसे बड़े जंगल की आग से जूझ रहा है, जिसमें ग्वाडलहारा में तेज़ गर्मी की लहर के बीच 32,000 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन तबाह हो गई है । आग की वजह से 34 गांवों को खाली कराना पड़ा , जबकि 200 से ज़्यादा फायरफाइटर्स , हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट आग बुझाने का काम जारी रखे हुए हैं। अधिकारियों ने इसे कैस्टिला-ला मांचा में सबसे बड़ी और स्पेन के इतिहास की दूसरी सबसे बड़ी जंगल की आग बताया । प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज़ ने इस आपदा को क्लाइमेट चेंज से जोड़ा , और ज़ोर दिया कि क्लाइमेट एक्शन को और मज़बूत करने की ज़रूरत है क्योंकि गर्मी की लहरें, सूखा और खराब मौसम पूरे यूरोप में जंगल की आग के खतरे को बढ़ा रहे हैं।
- राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रोमानिया दौरे के दौरान , भारत ने साइंस और टेक्नोलॉजी, इंडियन स्टडीज़ और स्पोर्ट्स में सहयोग से जुड़े तीन एग्रीमेंट साइन किए। दोनों देशों ने तीन साल के अंदर आपसी व्यापार को दोगुना करने पर भी सहमति जताई और 2028 को इंडिया-रोमानिया ईयर ऑफ़ इनोवेशन घोषित किया। इस पार्टनरशिप का मकसद AI, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग और एजुकेशन में सहयोग को मज़बूत करना है , साथ ही डिप्लोमैटिक रिश्तों के 80 साल पूरे होने का जश्न मनाना है।

- भारत ने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री तारिक रहमान को नई दिल्ली में BRICS समिट 2026 के लिए स्पेशल गेस्ट के तौर पर बुलाया है। हालांकि बांग्लादेश BRICS का सदस्य नहीं है, लेकिन यह न्योता ग्लोबल साउथ के लिए मज़बूत क्षेत्रीय सहयोग और सपोर्ट को दिखाता है। "क्रिएटिंग रेजिलिएंस, इनोवेशन, कोलेबोरेशन एंड सस्टेनेबिलिटी" थीम के तहत, भारत हेल्थ, क्लाइमेट रेजिलिएंस, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में सहयोग को बढ़ावा दे रहा है।
- भारत और इज़राइल ने नई दिल्ली में प्रस्तावित फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (FTA) के लिए बातचीत का दूसरा राउंड पूरा कर लिया है। बातचीत में सामान और सर्विस के ट्रेड, कस्टम, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, ओरिजिन के नियम और इन्वेस्टमेंट पर फोकस रहा। FY 2025-26 में दोनों देशों के बीच मर्चेंडाइज़ ट्रेड USD 3.93 बिलियन तक पहुंचने के साथ, इस एग्रीमेंट का मकसद मार्केट एक्सेस, टेक्नोलॉजी में सहयोग, इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन की मजबूती को बेहतर बनाना है।

बैंकिंग/अर्थव्यवस्था/व्यापार समाचार

- नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसीट (EGRs) लॉन्च किया है। यह SEBI द्वारा रेगुलेटेड डिजिटल सिस्टम है, जिससे फिजिकल गोल्ड की इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग होती है। EGRs का मतलब है स्टैंडर्ड, हाई-प्योरिटी गोल्ड का मालिकाना हक, जिसे अप्रूव्ड वॉल्ट मैनेजर के पास स्टोर किया जाता है। इससे इन्वेस्टर बिना फिजिकल स्टोरेज के डीमैट अकाउंट से सोना खरीद, बेच, रख और भुना सकते हैं। यह सिस्टम सुरक्षित स्टोरेज, ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, स्टैंडर्ड क्वालिटी और बेहतर लिक्विडिटी देता है। यह पहल भारत के बुलियन मार्केट को मॉडर्न बनाती है, ऑर्गनाइज़्ड गोल्ड ट्रेडिंग को मज़बूत करती है, प्राइस डिस्कवरी को बढ़ाती है और डिजिटल गोल्ड इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्टर का भरोसा बढ़ाती है।
- ऑफिस ऑफ़ इकोनॉमिक एडवाइजर (OEA), DPIIT के अनुसार, जून 2026 में भारत के इंडेक्स ऑफ़ कोर इंडस्ट्रीज (ICI) में साल-दर-साल 5% की ग्रोथ दर्ज की गई। सरकार ने एक रिवाइज्ड 2022-23 बेस ईयर पेश किया और आयरन ओर को नौवीं कोर इंडस्ट्री के तौर पर जोड़ा। आयरन ओर में सबसे ज़्यादा 43.9% की ग्रोथ दर्ज की गई, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और सीमेंट में 9.8% की ग्रोथ हुई, जबकि स्टील में 4.6% की ग्रोथ हुई। अप्रैल-जून 2026 के समय में 3.6% की ग्रोथ दर्ज की गई, जो मज़बूत इंडस्ट्रियल मोमेंटम दिखाता है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने 8 जून से 17 जुलाई 2026 के बीच पेमेंट बैलेंस को मज़बूत करने, रुपये को सपोर्ट करने और फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व बढ़ाने के मकसद से कुछ समय के लिए फॉरेक्स उपायों के ज़रिए $20.72 बिलियन की विदेशी पूंजी खींची। इस इनफ्लो में FCNR डिपॉज़िट में $17.41 बिलियन, एक्सटर्नल कमर्शियल बॉरोइंग (ECBs) के ज़रिए $1.34 बिलियन और ओवरसीज़ फॉरेन करेंसी बॉरोइंग (OFCBs) के ज़रिए $1.97 बिलियन शामिल थे। 10 जुलाई 2026 तक भारत का फॉरेक्स रिज़र्व $675.1 बिलियन था।
- EnKash ने भारत का पहला UPI-इनेबल्ड डिजिटल मील कार्ड लॉन्च किया, जो कर्मचारियों के मील बेनिफिट्स को यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (UPI) के साथ जोड़ता है। RuPay नेटवर्क पर फिजिकल और वर्चुअल दोनों फॉर्मेट में उपलब्ध, यह प्रीपेड कार्ड Swiggy, Zomato और Blinkit सहित 5 लाख से ज़्यादा फूड और ग्रोसरी आउटलेट्स पर टैप, स्वाइप, स्कैन और ऑनलाइन पेमेंट को सपोर्ट करता है। 1 अप्रैल 2026 से लागू होने वाले बदले हुए इनकम टैक्स नियमों के अनुसार, कर्मचारी हर महीने ₹8,800 तक के टैक्स-फ्री मील बेनिफिट्स पा सकते हैं, जिससे डिजिटल पेमेंट और कैशलेस ट्रांजैक्शन को बढ़ावा मिलेगा।
- FY24 और FY26 के बीच भारत का फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट लगभग 52% बढ़ा, जो 0.31 मिलियन टन से बढ़कर 0.47 मिलियन टन हो गया, जिसकी मुख्य वजह पोटैशियम सल्फेट, सुपरफॉस्फेट, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र और खास प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट था। इस दौरान ब्राज़ील सबसे बड़ा इंपोर्टर बनकर उभरा। एक्सपोर्ट ग्रोथ के बावजूद, भारत यूरिया, DAP और MOP के इंपोर्ट पर बहुत ज़्यादा निर्भर है, FY26 में कुल इंपोर्ट 28.17 मिलियन टन तक पहुँच गया, जो लंबे समय की एग्रीकल्चरल सिक्योरिटी के लिए इंपोर्ट पर निर्भरता कम करने की ज़रूरत को दिखाता है।
- रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया (RBI) ने सिक्योरिटी-ग्रेड पॉलीमर सबस्ट्रेट शीट के लिए BRBNMPL के ज़रिए ग्लोबल एक्सप्रेशन ऑफ़ इंटरेस्ट (EoI) मंगाकर अपने पॉलीमर बैंकनोट इनिशिएटिव को फिर से शुरू किया है। यह प्रपोज़ल टिकाऊ ₹10 और ₹20 के पॉलीमर नोट लाने पर फोकस करता है, जो नमी, गंदगी और फटने से बेहतर रेज़िस्टेंस देते हैं, साथ ही इनमें ट्रांसपेरेंट विंडो, होलोग्राम और रंग बदलने वाली इंक जैसे एडवांस्ड एंटी-नकली फ़ीचर भी शामिल हैं। हालांकि शुरू में ये ज़्यादा महंगे होते हैं, लेकिन पॉलीमर नोट ज़्यादा चलते हैं, जिससे बदलने का खर्च कम होता है और करेंसी को मॉडर्न बनाने में मदद मिलती है।
- वित्त मंत्रालय के अनुसार, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस (UPI) ने वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ₹314.23 लाख करोड़ के 24,161.69 करोड़ ट्रांज़ैक्शन रिकॉर्ड किए। NPCI द्वारा ऑपरेट किए जाने वाले इस प्लेटफ़ॉर्म के जून 2026 तक 55.49 करोड़ यूज़र थे, जो पिछले वित्त वर्ष की तुलना में काफ़ी बेहतर है। साइबर सिक्योरिटी को मज़बूत करने के लिए, अधिकारियों ने रिस्क-बेस्ड ट्रांज़ैक्शन लिमिट, बेहतर ऑथेंटिकेशन और कॉम्प्रिहेंसिव UPI इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी फ्रेमवर्क (CUISF) 2025 पेश किया। UPI ने इंटरनेशनल लेवल पर भी विस्तार किया, जिससे भूटान, सिंगापुर और UAE जैसे देशों में मर्चेंट पेमेंट मुमकिन हो गए।
- RBI के डेटा के मुताबिक, अप्रैल-मई FY27 के दौरान NRI डिपॉज़िट इनफ्लो 29.25% घटकर $1.33 बिलियन रह गया, जिसका मुख्य कारण FCNR(B) और NRE डिपॉज़िट में धीमी ग्रोथ है। मई 2026 में बकाया NRI डिपॉज़िट $165.96 बिलियन था, जबकि NRO डिपॉज़िट में मामूली बढ़ोतरी हुई। गिरावट के बाद, RBI ने नए FCNR(B) डिपॉज़िट के लिए एक रियायती स्वैप सुविधा शुरू की, जिसके परिणामस्वरूप 8 जून और 17 जुलाई 2026 के बीच $17.4 बिलियन का नया इनफ्लो हुआ, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ।

- इंफोसिस ने आशीष डैश को अपना अगला चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) और मैनेजिंग डायरेक्टर (MD) अपॉइंट किया है। यह 1 अप्रैल 2027 से लागू होगा। यह सलिल पारेख का दूसरा टर्म खत्म होने के बाद होगा। डैश, जो 1995 में इंफोसिस में शामिल हुए थे, कंपनी के पहले इंटरनली प्रमोटेड CEO बन गए हैं और उनके पास ग्लोबल बिजनेस ऑपरेशंस में लगभग तीन दशकों का अनुभव है। उनका अपॉइंटमेंट ऐसे समय में हुआ है जब IT इंडस्ट्री आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और डिजिटल इनोवेशन से तेज़ी से बदलाव के दौर से गुज़र रही है। लीडरशिप ट्रांज़िशन से इंफोसिस की लगातार ग्रोथ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट और लॉन्ग-टर्म कॉम्पिटिटिवनेस को सपोर्ट मिलने की उम्मीद है।
- भारत यूरोपियन इन्वेस्टर्स के लिए एक तेज़ी से बढ़ते कंज्यूमर मार्केट के तौर पर उभर रहा है, जो इसकी तेज़ इकोनॉमिक ग्रोथ, बढ़ते मिडिल क्लास, स्किल्ड वर्कफोर्स और बिज़नेस-फ्रेंडली सुधारों की वजह से हो रहा है। यूरैक्टिव के मुताबिक, टेक्नोलॉजी, रिन्यूएबल एनर्जी, हेल्थकेयर, मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल और फाइनेंशियल सर्विसेज़ जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट के बड़े मौके हैं। चीन में आने वाली चुनौतियों की तुलना में, भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और पॉलिसी सुधारों के ज़रिए लंबे समय तक ग्रोथ की ज़्यादा संभावना देता है। इस ट्रेंड से भारत-यूरोप ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप और एक लीडिंग ग्लोबल इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के तौर पर भारत की स्थिति मज़बूत होने की उम्मीद है।
- समुद्री रास्ते से उत्तर प्रदेश से दुबई तक 12.5 टन दशहरी और लंगड़ा आम सफलतापूर्वक एक्सपोर्ट किया, जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट में एक बड़ी कामयाबी है। ICAR-CISH और APEDA द्वारा डेवलप किए गए इस एक्सपोर्ट में METWASH ट्रीटमेंट, एडवांस्ड पोस्ट-हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी और बिना रुकावट वाली कोल्ड-चेन लॉजिस्टिक्स का इस्तेमाल किया गया, जिससे 25 दिन की यात्रा के बाद लगभग 90% मार्केटेबल क्वालिटी पक्की हुई। समुद्र पर आधारित इस प्रोटोकॉल से महंगे एयर फ्रेट पर डिपेंडेंस कम हुई और किसानों की कमाई ₹15-20 प्रति kg बढ़ गई, जिससे इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय आम एक्सपोर्ट बढ़ाने के नए मौके मिले।
- RBI के अनुसार, 17 जुलाई 2026 को खत्म हुए हफ़्ते में भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व $1.08 बिलियन बढ़कर $676.24 बिलियन हो गया। यह बढ़ोतरी मुख्य रूप से ज़्यादा फॉरेन करेंसी एसेट्स (FCAs) की वजह से हुई, हालांकि गोल्ड रिज़र्व में गिरावट आई। मज़बूत रिज़र्व रुपये की स्थिरता को बढ़ाते हैं, इम्पोर्ट को सपोर्ट करते हैं, इन्वेस्टर का भरोसा मज़बूत करते हैं, और भारत को ग्लोबल फाइनेंशियल अनिश्चितताओं का सामना करने में मदद करते हैं।
- SEBI की मंज़ूरी के बाद भारत 27 जुलाई 2026 से NSE पर अपना पहला बेंचमार्क-बेस्ड नैचुरल गैस फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च करेगा। NATGASIND के तहत ट्रेड होने वाला यह कॉन्ट्रैक्ट IGX दाहेज हब बेंचमार्क से जुड़ा है और प्रोड्यूसर, ट्रेडर और कंज्यूमर को गैस की कीमत में उतार-चढ़ाव से बचाव करने में मदद करता है। यह पहल प्राइस डिस्कवरी, ट्रांसपेरेंसी, रिस्क मैनेजमेंट को बेहतर बनाती है और भारत के गैस-बेस्ड इकॉनमी की ओर बदलाव में मदद करती है।

नियुक्तियाँ/इस्तीफ़े

- भारत सरकार ने सीनियर BJP लीडर हरजीत सिंह ग्रेवाल को नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ (NCM) का नया चेयरपर्सन अपॉइंट किया है। नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट, 1992 के तहत बनी यह कानूनी बॉडी माइनॉरिटी के अधिकारों की सुरक्षा करती है, संवैधानिक सुरक्षा को मॉनिटर करती है, और सरकार को भलाई के उपायों पर सलाह देती है। ग्रेवाल कमीशन को हेड करने वाले तीसरे सिख और पंजाब के दूसरे व्यक्ति बन गए हैं और उन्हें यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा मिला है। 1986 से BJP मेंबर, उन्होंने पहले BJP किसान मोर्चा शुरू किया और उसे लीड किया।
- ग्लोबल रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट फर्म हाइन्स ने अमित दीवान को एशिया-पैसिफिक और मिडिल ईस्ट ऑपरेशंस का हेड अपॉइंट किया है। पहले हाइन्स इंडिया को लीड कर रहे दीवान के पास रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट में लगभग 25 साल का एक्सपीरियंस है। वह हाई-ग्रोथ मार्केट में रीजनल इन्वेस्टमेंट, पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक एक्सपेंशन और क्रॉस-बॉर्डर ऑपरेशन्स को देखेंगे। जॉन तनाका की जगह लेने वाले दीवान, जो जापान और कोरिया पर फोकस करेंगे, उनकी नियुक्ति ग्लोबल लीडरशिप और इंटरनेशनल रियल एस्टेट मार्केट में इंडियन प्रोफेशनल्स के बढ़ते असर को दिखाती है।
- IRCTC के डायरेक्टर (टूरिज्म और मार्केटिंग) राहुल हिमालियन को संजय कुमार जैन के इस्तीफे के बाद चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर (CMD) का अतिरिक्त चार्ज दिया गया है। 1999 बैच के इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विस (IRTS) ऑफिसर, जिन्हें 26 साल से ज़्यादा का अनुभव है, हिमालियन फरवरी 2024 से IRCTC बोर्ड में काम कर रहे हैं। वे टिकटिंग, कैटरिंग, टूरिज्म, रेल नीर और हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज़ के लिए ज़िम्मेदार मिनीरत्न PSU में लीडरशिप कंटिन्यूटी सुनिश्चित करते हुए टूरिज्म और मार्केटिंग की देखरेख करते रहेंगे।
- सीनियर IAS ऑफिसर अनुराग जैन को कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमिटी (ACC) से मंज़ूरी मिलने के बाद NITI आयोग का नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर (CEO) बनाया गया है। 1989 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के ऑफिसर जैन के पास गवर्नेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल पॉलिसी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अनुभव है। वह दो साल या अगले ऑर्डर तक काम करेंगे, और विकसित भारत@2047 विज़न के तहत पॉलिसी सुधारों में मदद करेंगे और इन्वेस्टमेंट फ्रेंडलीनेस इंडेक्स 2026 जैसी पहलों को मज़बूत करेंगे।
- राजस्थान कैडर के 1994 बैच के IAS ऑफिसर नरेश पाल गंगवार को सरकार के एक बड़े फेरबदल के तहत शिक्षा मंत्रालय के तहत हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट का नया सेक्रेटरी बनाया गया है। कैबिनेट की अपॉइंटमेंट्स कमिटी (ACC) से मंज़ूरी मिलने के बाद, वे विनीत जोशी की जगह लेंगे, जिन्हें पंचायती राज डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। गंगवार हायर एजुकेशन पॉलिसी को लागू करने, इंस्टीट्यूशनल सुधार, यूनिवर्सिटी कोऑर्डिनेशन और रेगुलेटरी मामलों की देखरेख करेंगे। राज्य और केंद्र दोनों लेवल पर बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव अनुभव के साथ, उनसे भारत के हायर एजुकेशन सेक्टर में गवर्नेंस और सुधारों को मज़बूत करने की उम्मीद है।

- केंद्र सरकार ने 2005 बैच के IRS ऑफिसर सत्य पाल कुमार को फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट-इंडिया (FIU-इंडिया) का नया डायरेक्टर बनाया है। अपॉइंटमेंट्स कमिटी ऑफ़ कैबिनेट (ACC) से मंज़ूर इस अपॉइंटमेंट से मनी लॉन्ड्रिंग, टेरर फाइनेंसिंग, फाइनेंशियल फ्रॉड और संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन के खिलाफ भारत की कोशिशों को मज़बूती मिलेगी। FIU-इंडिया फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इकट्ठा करने और एनफोर्समेंट एजेंसियों के साथ शेयर करने में अहम भूमिका निभाता है।

रक्षा समाचार

- पारस डिफेंस एंड स्पेस टेक्नोलॉजीज की सब्सिडियरी कंपनी पारस सेमीकंडक्टर्स प्राइवेट लिमिटेड ने इंदौर-उज्जैन इलाके में ₹6,200 करोड़ की OSAT (आउटसोर्स्ड सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट) फैसिलिटी बनाने के लिए MP स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन के साथ एक MoU साइन किया है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन को सपोर्ट करते हुए, यह प्रोजेक्ट 3D इंटीग्रेशन, चिपलेट इंटीग्रेशन, हाइब्रिड बॉन्डिंग, वेफर बंपिंग और फ्लिप-चिप असेंबली जैसी एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। इससे 2,500 से ज़्यादा डायरेक्ट जॉब्स बनने की उम्मीद है, यह फैसिलिटी शुरू में डिफेंस, स्पेस, सेंसर और ऑप्टिकल सेक्टर्स को सर्विस देगी, फिर AI चिप पैकेजिंग में एक्सपैंड करेगी।
- इंडियन नेवी ने कोच्चि के सदर्न नेवल कमांड में ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 26-2 लॉन्च किया। यह पहली बार है जब भारत में मल्टीनेशनल मैरीटाइम एक्सरसाइज होस्ट की गई है। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज (CMF) के कंबाइंड टास्क फोर्स 154 (CTF 154) के तहत होने वाली इस एक्सरसाइज में 26 देशों के 254 पार्टिसिपेंट्स शामिल हैं। प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, सिम्युलेटर एक्सरसाइज और डिस्कशन के ज़रिए, इसका मकसद इंडियन ओशन रीजन में मैरीटाइम कोऑपरेशन, इंटरऑपरेबिलिटी, ऑपरेशनल रेडीनेस और रीजनल सिक्योरिटी को बढ़ाना है।
- नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल को भारत की नेशनल सिक्योरिटी में उनके खास योगदान के लिए तिलक स्मारक ट्रस्ट ने लोकमान्य तिलक नेशनल अवॉर्ड 2026 के लिए चुना है। यह अवॉर्ड 1 अगस्त 2026 को पुणे में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह देंगे। इंडियन पुलिस सर्विस (IPS) के पूर्व ऑफिसर और इंटेलिजेंस ब्यूरो के अनुभवी डोभाल को काउंटर-टेररिज्म, इंटेलिजेंस कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग और दशकों की शानदार पब्लिक सर्विस के ज़रिए भारत के राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा में उनकी लीडरशिप के लिए सम्मानित किया जा रहा है।
- समुद्र प्रदक्षिणा के साथ इतिहास रचा, यह देश का पहला तीनों सेनाओं का महिला दुनिया भर में यात्रा करने वाला अभियान था, जिसे भारतीय सेना, नौसेना और वायुसेना की नौ महिला अधिकारियों ने स्वदेशी IASV त्रिवेणी पर सवार होकर पूरा किया। 314 दिन की इस यात्रा में करीब 25,500 नॉटिकल मील की दूरी तय की गई, भूमध्य रेखा को दो बार पार किया गया, इंटरनेशनल डेट लाइन, सभी मेरिडियन को पार किया गया और केप ल्यूविन, केप हॉर्न और केप ऑफ गुड होप का चक्कर लगाया गया। इस मिशन ने आत्मनिर्भर भारत, नारी शक्ति, स्वदेशी जहाज निर्माण, समुद्री उत्कृष्टता और तीनों सेनाओं के बीच निर्बाध सहयोग को दिखाया।
- इंडियन नेवी ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत कारवार नेवल बेस पर INS मालवन, दूसरा माहे-क्लास एंटी-सबमरीन वारफेयर शैलो वॉटर क्राफ्ट (ASW-SWC) को कमीशन किया। कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा 80% से ज़्यादा स्वदेशी सामग्री के साथ बनाया गया यह जहाज़ एंटी-सबमरीन वारफेयर, अंडरवाटर सर्विलांस, माइन वारफेयर और कोस्टल सिक्योरिटी ऑपरेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है। महाराष्ट्र में मालवन के नाम पर रखा गया यह वॉरशिप समुद्री डोमेन अवेयरनेस को मज़बूत करता है, शैलो-वॉटर ऑपरेशनल क्षमता को बढ़ाता है, और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता को मज़बूत करता है।
- DRDO ने स्वदेशी AEW&C Mk-II प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए दो बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, जिससे आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत की एयर डिफेंस क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। CABS ने छह एयरबस A321 एयरक्राफ्ट को एयरबोर्न सर्विलांस प्लेटफॉर्म में बदलने के लिए AI इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड (AIESL) के साथ पार्टनरशिप की, जबकि अडानी डिफेंस सिस्टम्स एंड टेक्नोलॉजीज लिमिटेड (ADSTL) एडवांस्ड मिशन सिस्टम डेवलप करेगा। यह प्रोजेक्ट लंबी दूरी की निगरानी, अर्ली वॉर्निंग, सिक्योर कम्युनिकेशन और कमांड-एंड-कंट्रोल क्षमताएं देगा, जिससे स्वदेशी एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग और इंडियन एयर फोर्स की ऑपरेशनल तैयारी मजबूत होगी।
- हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) और सफ्रान एयरक्राफ्ट इंजन्स ने दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले CFM LEAP एयरक्राफ्ट इंजन के लिए सुपरलॉय टर्बाइन रिंग फोर्जिंग बनाने के लिए एक लॉन्ग-टर्म एग्रीमेंट साइन किया है। प्रोडक्शन बेंगलुरु में HAL के फाउंड्री और फोर्ज डिवीजन में होगा, जो एयरबस A320neo, बोइंग 737 MAX, और COMAC C919 जैसे एयरक्राफ्ट के लिए कंपोनेंट्स सप्लाई करेगा। यह पार्टनरशिप भारत के एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को बेहतर बनाती है, हाई-वैल्यू कंपोनेंट्स के एक्सपोर्ट को बढ़ाती है, ग्लोबल सप्लाई चेन इंटीग्रेशन को मजबूत करती है, और ग्लोबल एयरोस्पेस मैन्युफैक्चरिंग हब बनने के भारत के एम्बिशन को सपोर्ट करती है।
- DRDO ने 23 जुलाई 2026 को ओडिशा के डॉ. APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से स्वदेशी कुशा लॉन्ग-रेंज सरफेस-टू-एयर मिसाइल (LR-SAM) का पहला फ्लाइट टेस्ट सफलतापूर्वक किया। मिसाइल ने एक हाई-स्पीड एरियल टारगेट को सटीक रूप से इंटरसेप्ट किया, जिससे इसकी एडवांस्ड एयर डिफेंस क्षमता साबित हुई। एडवांस्ड रडार, कमांड-एंड-कंट्रोल सिस्टम और स्वदेशी टेक्नोलॉजी से लैस यह सिस्टम एयरक्राफ्ट, मिसाइल और UAV का मुकाबला कर सकता है। यह सफल ट्रायल आत्मनिर्भर भारत को मजबूत करता है, भारत के इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस नेटवर्क को बढ़ाता है, और ऑपरेशनल डिप्लॉयमेंट की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति को दिखाता है।
- 350 kg थ्रस्ट कैटेगरी में अपना पहला स्वदेशी एक्सपेंडेबल टर्बोजेट इंजन बनाया है, जिसे GTRE-DRDO ने डिज़ाइन किया है और आज़ाद इंजीनियरिंग ने बनाया है। 24 महीनों में डिलीवर होने वाला यह इंजन मिसाइलों, UAVs और एंटी-ड्रोन सिस्टम के लिए है। यह उपलब्धि भारत की स्वदेशी प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देती है, विदेशी इंजनों पर निर्भरता कम करती है, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर के बीच सफल सहयोग को दिखाती है। यह आत्मनिर्भर भारत और भारत की एडवांस्ड एयरोस्पेस और डिफेंस क्षमताओं को मजबूत करने में एक बड़ा मील का पत्थर है।

पुरस्कार और सम्मान

- उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में हुए 58वें इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड (IChO) 2026 में एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की, जिसमें चारों पार्टिसिपेंट्स ने पहली बार गोल्ड मेडल जीते। देबदत्त प्रियदर्शी, हर्षित सिंगला, कबीर छिल्लर और संदीप कुची ने गोल्ड मेडल जीते, जिससे भारत चीन, वियतनाम और रूस के इंडिविजुअल पार्टिसिपेंट्स ग्रुप B के साथ टॉप परफॉर्म करने वाले देशों में शामिल हो गया। 93 देशों के 363 स्टूडेंट्स के साथ ऑर्गनाइज़ इस कॉम्पिटिशन में एडवांस्ड केमिस्ट्री कॉन्सेप्ट्स और लैबोरेटरी स्किल्स को टेस्ट किया गया। यह उपलब्धि HBCSE की कड़ी साइंटिफिक ट्रेनिंग की बेहतरीन क्वालिटी को दिखाती है।
- लिथुआनिया के विलनियस में हुए 37वें इंटरनेशनल बायोलॉजी ओलंपियाड (IBO) 2026 में एक गोल्ड और तीन सिल्वर मेडल जीते। भव्य गुणवाल ने गोल्ड मेडल जीता, जबकि सौमिल मैती, निशित कलानी और अनमोल कुमार ने सिल्वर मेडल जीते, जिससे यह पक्का हुआ कि हर भारतीय पार्टिसिपेंट को अवॉर्ड मिले। इस इवेंट में 78 देशों के 307 स्टूडेंट्स ने हिस्सा लिया, जिन्होंने जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इकोलॉजी और फिजियोलॉजी में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल नॉलेज को परखा। HBCSE-TIFR के गाइडेंस में, भारत ने ग्लोबल साइंस कॉम्पिटिशन में अपनी रेप्युटेशन और मजबूत की।
- मशहूर अमेरिकन फिल्ममेकर जेम्स ग्रे को 9 अगस्त 2026 को 79वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में पार्डो अल्ला कैरियरा (ऑनरेरी करियर पार्डो अवॉर्ड) मिलेगा। यह सम्मान वर्ल्ड सिनेमा में उनके शानदार योगदान को पहचान देता है और उनकी नई फिल्म पेपर टाइगर की स्क्रीनिंग से पहले दिया जाएगा। ग्रे को लिटिल ओडेसा, वी ओन द नाइट, द इमिग्रेंट, द लॉस्ट सिटी ऑफ़ Z, एड एस्ट्रा और आर्मगेडन टाइम जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है, जिन्हें पहचान, परिवार, इमिग्रेशन और इंसानी मूल्यों को दिखाने के लिए जाना जाता है।

योजना समाचार

- दिल्ली सरकार ने BS-IV और पुरानी कमर्शियल गाड़ियों को BS-VI या इलेक्ट्रिक गाड़ियों से बदलने के लिए परिवर्तन स्कीम को मंज़ूरी दी है, जिससे पूरे नेशनल कैपिटल रीजन (NCR) में एयर पॉल्यूशन कम होगा। इस स्कीम में 10 साल के मोटर व्हीकल टैक्स में छूट, रजिस्ट्रेशन फीस में छूट, इंटरेस्ट सब्सिडी, मैन्युफैक्चरर डिस्काउंट, फ्यूल वाउचर, और पेंडिंग टैक्स और फाइन में छूट जैसे इंसेंटिव दिए जा रहे हैं। लगभग 2.7 लाख ट्रक और बस ऑपरेटरों को फायदा होने की उम्मीद है, जो दिल्ली EV पॉलिसी 2026 और साफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट को सपोर्ट करेंगे।
- मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ सरकार के मुख्यमंत्री विष्णु देव साई के नेतृत्व में शुरू किए गए स्वस्थ बस्तर अभियान ने सुकमा में माँ और बच्चे की हेल्थकेयर में काफ़ी सुधार किया है। यह पहल बचाव वाली हेल्थकेयर, बीमारी का जल्दी पता लगाना, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी, प्रसव से पहले की देखभाल, वैक्सीनेशन और घर-घर जाकर मेडिकल सर्विस देने पर फोकस करती है। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी बढ़कर 98.6% हो गई है, जबकि माँ और बच्चे की मौत की दर में कमी आई है। इस प्रोग्राम ने दूर-दराज के आदिवासी, जंगल और नक्सल प्रभावित इलाकों में हेल्थकेयर की पहुँच बढ़ाई है, जिससे हेल्थकेयर के नतीजे बेहतर हुए हैं।
- कर्नाटक की गृह ज्योति स्कीम के तहत घर के मालिकों और किराएदारों समेत एलिजिबल घरेलू कंज्यूमर्स को हर महीने 200 यूनिट तक फ्री बिजली मिलती है। इस पहल का मकसद घर के बिजली के खर्च को कम करना और परिवारों को बचत को पढ़ाई और हेल्थकेयर पर खर्च करने की इजाज़त देकर जीवन स्तर को बेहतर बनाना है। एप्लीकेंट्स को आधार को बिजली अकाउंट डिटेल्स से लिंक करना होगा और तय कंजम्प्शन लिमिट को पूरा करना होगा। एप्लीकेशन सेवा सिंधु पोर्टल या ESCOM वेबसाइट्स के ज़रिए जमा किए जाते हैं, जिससे पूरे कर्नाटक में सस्ती बिजली की पहुंच को बढ़ावा मिलता है।
- राजस्थान की मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना (MAAY) हर परिवार को हर साल ₹25 लाख तक का कैशलेस हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज देती है। पहले इसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के नाम से जाना जाता था, इसमें 1,700 से ज़्यादा मेडिकल और सर्जिकल प्रोसीजर, एक्सीडेंट इंश्योरेंस, और हॉस्पिटल में भर्ती होने से पहले और बाद के खर्चे शामिल हैं। जन आधार कार्ड पर लिस्टेड सभी सदस्य, जिनमें नए जन्मे बच्चे भी शामिल हैं, बिना किसी उम्र की लिमिट के इसके लिए एलिजिबल हैं। यह स्कीम हेल्थकेयर का खर्च कम करती है, मेडिकल एक्सेस को बेहतर बनाती है, और परिवारों को गंभीर बीमारियों की वजह से होने वाली पैसे की तंगी से बचाती है।
- डिजिटल इंडिया मिशन के तहत कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) स्कीम लोगों को विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर (VLE) बनने और घर से डिजिटल सर्विस सेंटर चलाने में मदद करती है। CSC 4.0 के तहत, आधार, पैन, आयुष्मान भारत, बैंकिंग, इंश्योरेंस, बिल पेमेंट और सर्टिफिकेट समेत 500 से ज़्यादा सरकारी और प्राइवेट सर्विस उपलब्ध हैं। एप्लिकेंट के पास क्लास 10 की क्वालिफिकेशन, बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी और TEC सर्टिफिकेशन होना चाहिए। यह पहल डिजिटल इन्क्लूजन, रूरल एंटरप्रेन्योरशिप और इनकम के मौकों को बढ़ावा देती है, जिससे हर महीने ₹30,000 से ज़्यादा की कमाई हो सकती है।
- मिनी नंदी किसान समृद्धि स्कीम, गिर, साहीवाल और थारपारकर जैसी देसी नस्लों का इस्तेमाल करके 10 गायों की डेयरी यूनिट बनाने के लिए फाइनेंशियल मदद देकर साइंटिफिक डेयरी फार्मिंग को सपोर्ट करती है। यह स्कीम ₹11.80 लाख तक की 50% सरकारी सब्सिडी देती है, जिसमें 15% बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन और 35% बैंक लोन सपोर्ट शामिल है। कम से कम 50% बेनिफिशियरी महिलाएं हैं, जो ग्रामीण एंटरप्रेन्योरशिप और महिला एम्पावरमेंट को बढ़ावा देती हैं। इस पहल का मकसद दूध का प्रोडक्शन बढ़ाना, देसी मवेशियों की नस्लों को बचाना और ट्रांसपेरेंट ऑनलाइन एप्लीकेशन के ज़रिए किसानों की रोजी-रोटी को बेहतर बनाना है।
- कर्नाटक उद्योगिनी स्कीम महिला एंटरप्रेन्योर्स को सरकारी सब्सिडी के साथ बैंकों के ज़रिए ₹3 लाख तक का बिना गारंटी वाला लोन देकर सपोर्ट करती है। इसे कर्नाटक स्टेट विमेन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन (KSWDC) मैनेज करता है, यह रिटेल, टेलरिंग, मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग और सर्विसेज़ के बिज़नेस को कवर करता है। बेनिफिशियरी को एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम (EDP) ट्रेनिंग भी मिलती है। यह स्कीम SC/ST महिलाओं के लिए 50% और दूसरों के लिए 30% सब्सिडी देती है, जिससे पूरे कर्नाटक में सेल्फ-एम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और सस्टेनेबल रोजी-रोटी को बढ़ावा मिलता है।

- थायी भाग्य स्कीम कर्नाटक में आर्थिक रूप से कमज़ोर गर्भवती महिलाओं को मुफ़्त कैशलेस मैटरनिटी केयर देती है। इसमें नॉर्मल और सिज़ेरियन डिलीवरी, दवाएँ, ट्रांसपोर्टेशन, प्रसव से पहले और बाद की देखभाल, और सरकारी और रजिस्टर्ड प्राइवेट अस्पतालों में इलाज शामिल है। एलिजिबल BPL, SC, और ST महिलाएँ अपनी पहली दो डिलीवरी के लिए फ़ायदे उठा सकती हैं। इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी और अच्छी हेल्थकेयर को बढ़ावा देकर, इस पहल का मकसद माँ और बच्चे की मौत की दर को कम करना है, साथ ही बिना पैसे के बोझ के सुरक्षित डिलीवरी सुनिश्चित करना है।
- राजस्थान की मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना (MMYSY) 2026 का मकसद हर साल एक लाख एंटरप्रेन्योर बनाना है। इसके लिए ₹10 लाख तक का लोन बिना ब्याज और बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। 31 मार्च 2029 तक चलने वाली यह स्कीम मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज़, IT, फ़ूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल और ट्रेडिंग सेक्टर को सपोर्ट करती है। सरकार पूरा ब्याज खर्च उठाती है और क्रेडिट गारंटी फीस वापस करती है। 18-45 साल के योग्य निवासियों को RSLDC के ज़रिए एंटरप्रेन्योरशिप ट्रेनिंग भी मिलती है, जिससे युवाओं को नौकरी ढूंढने के बजाय नौकरी देने वाले बनने के लिए बढ़ावा मिलता है।
- कर्नाटक कृषि अरण्य प्रोत्साहन योजना (KAPY) किसानों को तीन साल तक पेड़ के पौधों की देखभाल करने के लिए इंसेंटिव देकर एग्रोफॉरेस्ट्री अपनाने के लिए बढ़ावा देती है। किसानों को हर बचे हुए पौधे के लिए लगातार सालों में ₹35, ₹40, और ₹50 मिलते हैं। यह योजना बायोडायवर्सिटी, कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, क्लाइमेट-रेज़िलिएंट खेती, और लकड़ी, फल, चारा, और जंगल के प्रोडक्ट्स के ज़रिए एक्स्ट्रा इनकम को बढ़ावा देती है, साथ ही राज्य के ग्रीन कवर को भी बढ़ाती है।

खेल समाचार

- स्पेन ने न्यू जर्सी के मेटलाइफ स्टेडियम में एक्स्ट्रा टाइम के बाद अर्जेंटीना को 1-0 से हराकर FIFA वर्ल्ड कप 2026 जीता। फेरान टोरेस ने 106वें मिनट में विनिंग गोल किया, जिससे स्पेन को 2010 के बाद दूसरा वर्ल्ड कप टाइटल मिला। कोच लुइस डे ला फुएंते के अंडर, स्पेन ने पूरे टूर्नामेंट में सिर्फ़ एक गोल खाया, जिससे चैंपियंस का डिफेंसिव रिकॉर्ड बना। USA, मैक्सिको और कनाडा में होस्ट किए गए 48 टीमों के इस बड़े टूर्नामेंट ने अरबों दर्शकों को अट्रैक्ट किया और स्पेन का टैक्टिकल दबदबा दिखाया।
- काइलियन एम्बाप्पे FIFA वर्ल्ड कप के इतिहास में सबसे ज़्यादा गोल करने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। उन्होंने 2026 टूर्नामेंट में 22 गोल करके लियोनेल मेसी के 21 गोल के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। तीन वर्ल्ड कप में यह मुकाम हासिल करते हुए, इस फ्रेंच स्टार ने मिरोस्लाव क्लोस, रोनाल्डो नाज़ारियो, गर्ड मुलर, पेले, हैरी केन और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गज खिलाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। सिर्फ़ 27 साल की उम्र में, एम्बाप्पे के पास अपना शानदार रिकॉर्ड बढ़ाने और फुटबॉल के अब तक के सबसे महान खिलाड़ियों में अपनी जगह मज़बूत करने के कई मौके हैं।
- रोहित शर्मा 19 जुलाई, 2026 को लॉर्ड्स में ODI सेंचुरी बनाने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर बने। 39 साल और 80 दिन की उम्र में बनाया गया उनका 34वां ODI सेंचुरी, उन्हें सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए भारत का सबसे उम्रदराज इंटरनेशनल सेंचुरी बनाने वाला खिलाड़ी बनाता है। रोहित इंग्लैंड में आठ ODI सेंचुरी के साथ एक ही देश में सबसे सफल विज़िटिंग बैट्समैन भी बन गए। विराट कोहली के साथ, उन्होंने अपने 400वें इंटरनेशनल मैच में 113 रन की पार्टनरशिप की, जिससे एक और बड़ा माइलस्टोन बना।
- लियोनेल मेसी तीन FIFA वर्ल्ड कप फाइनल में खेलने वाले पहले फुटबॉलर बन गए, उन्होंने स्पेन के खिलाफ 2026 के फाइनल में यह उपलब्धि हासिल की। वे पिछली बार 2014 और 2022 में फाइनल में पहुंचे थे, और उन्होंने कैफू को पीछे छोड़ दिया, जो सिर्फ दो फाइनल में खेले थे। हालांकि अर्जेंटीना एक्स्ट्रा टाइम के बाद 1-0 से हार गया, लेकिन मेसी ने आठ गोल और चार असिस्ट के साथ एक शानदार टूर्नामेंट खेला, जिससे लगातार वर्ल्ड कप खिताब जीतने का मौका चूकने के बावजूद फुटबॉल के सबसे महान खिलाड़ियों में से एक के रूप में उनकी पहचान और मजबूत हुई।
- पीवी सिंधु ने BWF जापान ओपन 2026 जीता, और BWF सुपर 750 टाइटल जीतने वाली पहली भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी बन गईं। उन्होंने अकाने यामागुची को हराया। 21-17, 21-17 से टोक्यो में जीत हासिल की, जो 2019 वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद उनका पहला बड़ा टाइटल है। 31 साल की उम्र में, सिंधु सुपर 750 इवेंट जीतने वाली सबसे उम्रदराज महिला भी बन गईं। इस जीत से उनकी वर्ल्ड रैंकिंग 18वें से 9वें नंबर पर आ गई, जिससे BWF वर्ल्ड चैंपियनशिप से पहले उनकी वापसी पक्की हो गई।
- FIFA वर्ल्ड कप 2030, टूर्नामेंट की 100वीं सालगिरह को एक ऐतिहासिक मल्टी-कॉन्टिनेंट फ़ॉर्मेट के साथ मनाएगा। स्पेन, पुर्तगाल और मोरक्को मुख्य होस्ट होंगे, जबकि उरुग्वे, अर्जेंटीना और पैराग्वे सौ साल पूरे होने पर ओपनिंग मैच खेलेंगे। 8 जून से 21 जुलाई, 2030 तक (FIFA के कन्फ़र्मेशन पर निर्भर) होने वाले इस इवेंट में 48 टीमों का एक बड़ा फ़ॉर्मेट होगा, जिसमें छह ऑटोमैटिक होस्ट बर्थ शामिल हैं। यह तीन कॉन्टिनेंट और छह देशों में होस्ट किया जाने वाला पहला पुरुषों का वर्ल्ड कप बन जाएगा।
- वें कॉमनवेल्थ गेम्स 2026, 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक स्कॉटलैंड के ग्लासगो में होंगे। इसमें 74 कॉमनवेल्थ देश, 10 खेल और 215 गोल्ड मेडल इवेंट होंगे। भारत ने 120 सदस्यों वाले दल की घोषणा की है, जिसमें नीरज चोपड़ा, मीराबाई चानू, लवलीना बोरगोहेन, श्रीहरि नटराज और मुरली श्रीशंकर जैसे मेडल के बड़े दावेदार शामिल हैं। मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन भारत के फ्लैग बेयरर होंगे, जबकि कॉम्पिटिशन ग्लासगो के बड़े स्पोर्टिंग वेन्यू पर होंगे।
- फ्रांस के लेस मेन्यूइर्स में मेन्यूइर्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2026 में भारत का दबदबा रहा, जिसमें ग्रैंडमास्टर एस. रोहित कृष्णा ने गोल्ड मेडल जीता और ग्रैंडमास्टर राजा ऋत्विक ने सिल्वर मेडल जीता। दोनों बिना हारे रहे, नौ राउंड में 7 पॉइंट बनाए, जिसमें रोहित ने बेहतर टाई-ब्रेक स्कोर पर टाइटल जीता। फाइनल राउंड में मैक्सिम लेगार्ड पर ऋत्विक की जीत टूर्नामेंट की खास बात थी, जिसने कॉम्पिटिटिव चेस में भारत की बढ़ती ताकत और इंटरनेशनल पहचान को और पक्का किया।

- स्कॉटलैंड के राष्ट्रीय जानवर—यूनिकॉर्न से प्रेरित फिनी को ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑफिशियल मैस्कॉट के तौर पर पेश किया गया है। ग्लासगो के मशहूर फिनिएस्टन क्रेन के नाम पर रखा गया यह मैस्कॉट स्कॉटिश कल्चर, लोकगीत, क्रिएटिविटी और कम्युनिटी स्पिरिट को दिखाता है। फिनी एजुकेशनल प्रोग्राम, पब्लिक एंगेजमेंट एक्टिविटी और टूरिज्म कैंपेन के ज़रिए गेम्स को प्रमोट करेगा, साथ ही इवेंट के लिए एक यादगार पहचान बनाएगा और लोकल परंपराओं को पूरे कॉमनवेल्थ के एथलीट और दर्शकों से जोड़ेगा।
- भारतीय ग्रैंडमास्टर एस. रोहित कृष्णा ने फ्रांस में मेन्यूयर्स इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप 2026 में गोल्ड मेडल जीता, जबकि ग्रैंडमास्टर राजा ऋत्विक ने सिल्वर मेडल जीता। दोनों खिलाड़ी बिना हारे रहे, 9 राउंड में 7 पॉइंट बनाए, जिसमें रोहित ने बेहतर टाई-ब्रेक स्कोर से जीत हासिल की। मैक्सिम लेगार्ड पर ऋत्विक की आखिरी राउंड की जीत एक बड़ी हाइलाइट थी। उनके शानदार प्रदर्शन ने इंटरनेशनल चेस में भारत के बढ़ते दबदबे और देश के ग्लोबल चेस पावरहाउस के रूप में उभरने को और मज़बूत किया है।
- EU के बैन के बाद अर्कादी ड्वोरकोविच के हटने के बाद विश्वनाथन आनंद ने FIDE के अंतरिम प्रेसिडेंट का पद संभाला। FIDE के डिप्टी प्रेसिडेंट के तौर पर, आनंद समरकंद में सितंबर 2026 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन तक ऑर्गनाइज़ेशन को देखेंगे। लीडरशिप ट्रांज़िशन ग्लोबल चेस एडमिनिस्ट्रेशन में कंटिन्यूटी पक्का करता है और साथ ही चल रहे डेवलपमेंट इनिशिएटिव को भी बनाए रखता है। आनंद का अपॉइंटमेंट एक ऐतिहासिक माइलस्टोन है, जिससे भारतीय चेस लेजेंड एक ज़रूरी ट्रांज़िशन पीरियड के दौरान चेस के लिए दुनिया की गवर्निंग बॉडी को गाइड करने के लिए ज़िम्मेदार बन गए हैं।
- भारत के वैभव सूर्यवंशी ज़िम्बाब्वे के खिलाफ पहले T20I मैच में सिर्फ़ 15 साल और 118 दिन की उम्र में T20I में फिफ्टी बनाने वाले सबसे कम उम्र के बैट्समैन बन गए। उन्होंने 263 से ज़्यादा के ज़बरदस्त स्ट्राइक रेट से 19 गेंदों में हाफ सेंचुरी बनाई और लुइस ब्रूस का पिछला रिकॉर्ड तोड़ दिया। यह युवा लेफ्टहैंडर यह माइलस्टोन हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय और ICC फुल मेंबर देश के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी भी बन गए, जिससे भारत की उभरती हुई क्रिकेट प्रतिभा का पता चलता है।
- लवलीना बोरगोहेन ने ग्लासगो में महिलाओं की 75 kg बॉक्सिंग के सेमीफ़ाइनल में पहुँचकर कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारत के लिए पहला मेडल पक्का किया। इस कैटेगरी में सिर्फ़ पाँच पार्टिसिपेंट्स होने की वजह से, सभी सेमीफ़ाइनलिस्ट का मेडल पक्का हो गया। 2018 और 2022 में पोडियम से चूकने के बाद यह लवलीना का पहला कॉमनवेल्थ गेम्स मेडल था। इस इवेंट में शानदार फ़ॉर्म में उतरते हुए, वह फ़ाइनल में पहुँचकर अपने पक्के मेडल को अपग्रेड करने के मौके के साथ तारोना ताफ़ाकी का सामना करेंगी।
- कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 स्कॉटलैंड के ग्लासगो में स्कॉटिश कल्चर और विरासत का जश्न मनाने वाले एक रंगीन समारोह के साथ ऑफिशियली शुरू हुए। मीराबाई चानू और लवलीना बोरगोहेन ने फ्लैग बियरर के तौर पर भारतीय दल को लीड किया, जबकि किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला इस इवेंट में शामिल हुए। कॉम्पिटिशन चार जगहों पर होंगे, हालांकि बैडमिंटन, शूटिंग और रेसलिंग जैसे खेल नहीं होंगे। ऑफिशियल मैस्कॉट फिनी, जो स्कॉटिश विरासत से प्रेरित है, गेम्स की भावना और पहचान को दिखाता है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी समाचार

- भारत ने 20 जुलाई, 2026 को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया (DCGI) से मंज़ूरी मिलने के बाद, देश की पहली डेंगू वैक्सीन QDENGA (TAK-003) को मंज़ूरी दे दी है। जापान की टेकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स की बनाई यह लाइव-एटेन्यूएटेड टेट्रावैलेंट वैक्सीन, डेंगू वायरस के सभी चार सीरोटाइप (DENV-1 से DENV-4) से बचाती है और इसे 4-60 साल के लोगों के लिए मंज़ूरी दी गई है, चाहे उन्हें पहले कोई इन्फेक्शन हुआ हो या नहीं। बायोलॉजिकल E इस वैक्सीन को देश में ही बनाएगी, जिसकी सालाना क्षमता 50 मिलियन डोज़ होगी, जिससे डेंगू के खिलाफ भारत की लड़ाई में मदद मिलेगी और गंभीर इन्फेक्शन कम होंगे।
- भारत ने वन नेशन, वन टाइम पहल को आगे बढ़ाते हुए व्हाइट रैबिट टेक्नोलॉजी पर आधारित इंडियन स्टैंडर्ड टाइम (IST) डिसेमिनेशन नेटवर्क शुरू किया। डिपार्टमेंट ऑफ़ कंज्यूमर अफेयर्स, CSIR-NPL और ISRO का बनाया यह स्वदेशी सिस्टम फाइबर -ऑप्टिक नेटवर्क पर सब-नैनोसेकंड एक्यूरेसी के साथ UTC (NPLI)-ट्रेसेबल IST देता है। यह बैंकिंग, फाइनेंशियल मार्केट, टेलीकम्युनिकेशन, पावर ग्रिड, साइबर सिक्योरिटी और ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुरक्षित और सटीक टाइम सिंक्रोनाइज़ेशन पक्का करता है। RRSL बेंगलुरु और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के सफल डेमोंस्ट्रेशन ने इसके भरोसे को दिखाया और भारत की टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता को मज़बूत किया।
- IIT कानपुर, UPNEDA की मदद से उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इनोवेटिव और इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम पर सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (ECOGEN) बना रहा है। यह सेंटर प्रोडक्शन, स्टोरेज, इस्तेमाल और सिस्टम इंटीग्रेशन समेत पूरी ग्रीन हाइड्रोजन वैल्यू चेन पर फोकस करेगा। इसका मकसद सस्ती हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी डेवलप करना, स्टोरेज सॉल्यूशन को बेहतर बनाना, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को बढ़ावा देना, फॉसिल फ्यूल पर निर्भरता कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी को अपनाने को मज़बूत करना और भारत के लंबे समय के नेट-ज़ीरो और क्लीन एनर्जी लक्ष्यों को सपोर्ट करना है।
- भारत ने टेकेडा बायोफार्मास्युटिकल्स की बनाई QDENGA को पब्लिक इस्तेमाल के लिए अपनी पहली डेंगू वैक्सीन के तौर पर मंज़ूरी दी है। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया (DCGI) से मंज़ूरी मिली यह वैक्सीन सभी चार डेंगू वायरस सीरोटाइप (DENV-1 से DENV-4) से बचाती है और इसे 4-60 साल के लोगों के लिए मंज़ूरी दी गई है, इसके लिए प्री-वैक्सीनेशन स्क्रीनिंग की ज़रूरत नहीं है। भारत की TIDES फेज़ III स्टडी सहित 28,000 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स वाले ग्लोबल क्लिनिकल ट्रायल्स से सपोर्टेड, यह वैक्सीन डेंगू इन्फेक्शन और हॉस्पिटलाइज़ेशन को काफ़ी कम करती है, जिससे भारत की बीमारी रोकने की स्ट्रैटेजी मज़बूत होती है।
- इंडियन काउंसिल ऑफ़ मेडिकल रिसर्च (ICMR) ने मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र पहल के तहत तीन देसी हेल्थकेयर टेक्नोलॉजी एमक्योर फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड और बायोलॉजिकल ई लिमिटेड को ट्रांसफर कीं। इनमें HPV से जुड़े सर्वाइकल प्रीकैंसर के इलाज के लिए SHetA2, एक फ्यूजन प्रोटीन-बेस्ड टाइफाइड वैक्सीन, और साल्मोनेला टाइफी, साल्मोनेला पैराटाइफी, और शिगेला को टारगेट करने वाली एक रिकॉम्बिनेंट मल्टीवैलेंट वैक्सीन शामिल हैं। यह टेक्नोलॉजी ट्रांसफर मेक इन इंडिया को बढ़ावा देता है, बायोटेक्नोलॉजी इनोवेशन को मजबूत करता है, सस्ती हेल्थकेयर को सपोर्ट करता है, और देसी मेडिकल रिसर्च के कमर्शियलाइजेशन को तेज करता है।

- IIT कानपुर, उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी 2024 के तहत ग्रीन हाइड्रोजन के लिए इनोवेटिव और इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम पर सेंटर ऑफ़ एक्सीलेंस (ECOGEN) बना रहा है । यह सेंटर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, स्टोरेज, इस्तेमाल और सिस्टम इंटीग्रेशन पर फोकस करेगा , और कॉस्ट-इफेक्टिव क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन को सपोर्ट करेगा। रिसर्च, इंडस्ट्री में सहयोग और स्किल डेवलपमेंट को बढ़ावा देकर, ECOGEN का मकसद कार्बन एमिशन कम करना, रिन्यूएबल एनर्जी अपनाने को मज़बूत करना, भारत के नेट-ज़ीरो लक्ष्यों को सपोर्ट करना और उत्तर प्रदेश को एक बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन इनोवेशन हब बनाना है।
- एमएसीएस अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे के वैज्ञानिकों ने पश्चिमी घाट में पांच नई एलोग्राफा लाइकेन प्रजातियों की खोज की , जो इस क्षेत्र में इस जीनस का पहला व्यापक आणविक अध्ययन है। नई पहचानी गई प्रजातियाँ- एलोग्राफा केरालेंसिस , ए. नायके , ए. पैराकोनसांगुनीया , ए. पर्सिस्टिनस्पर्सा , और ए. सेमीकार्बोनिसाटा — की पुष्टि फील्ड सर्वे, DNA सीक्वेंसिंग, केमिकल एनालिसिस और मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ से की गई। चूंकि लाइकेन पर्यावरण स्वास्थ्य के महत्वपूर्ण बायोइंडिकेटर हैं , इसलिए यह खोज दुनिया के सबसे समृद्ध बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में से एक में बायोडायवर्सिटी रिसर्च, इकोसिस्टम मॉनिटरिंग और संरक्षण को मजबूत करती है।
- क्लाउड फैबल 5 , हार्वर्ड के मैथमैटिशियन लेवेंट एल्पोगे और एंथ्रोपिक से जुड़ी एक AI-असिस्टेड मैथमेटिकल सफलता ने 1939 में प्रपोज़ किए गए लंबे समय से चले आ रहे जैकोबियन कंजेक्चर को चुनौती दी है । AI ने कथित तौर पर एक काउंटरएग्जांपल की पहचान की , जिसे बाद में SymPy और लीन प्रूफ असिस्टेंट का इस्तेमाल करके वेरिफाई किया गया। अगर इंडिपेंडेंट पीयर रिव्यू से कन्फर्म होता है, तो यह खोज अलजेब्रिक ज्योमेट्री , पॉलीनोमियल मैपिंग और कम्प्यूटेशनल मैथमेटिक्स को बदल सकती है, साथ ही मैथमेटिकल रिसर्च, थ्योरम एक्सप्लोरेशन और फॉर्मल प्रूफ वेरिफिकेशन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बढ़ती भूमिका को भी दिखा सकती है ।
- IIT मद्रास 1-2 अगस्त को MeitY और RISC-V इंटरनेशनल के साथ मिलकर “भारत के सेमीकंडक्टर भविष्य को सशक्त बनाना” थीम के तहत तीसरे डिजिटल इंडिया RISC-V (DIR-V) सिम्पोजियम 2026 की मेजबानी करेगा । सिम्पोजियम में पॉलिसीमेकर्स, रिसर्चर्स, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री लीडर्स, इन्वेस्टर्स और स्टूडेंट्स RISC-V आर्किटेक्चर, सेमीकंडक्टर डिज़ाइन, AI, सिक्योर कंप्यूटिंग और हार्डवेयर इनोवेशन पर चर्चा करने के लिए एक साथ आएंगे । एक बड़ा आकर्षण DIR-V ग्रैंड चैलेंज हैकथॉन होगा , जो भारत के सेमीकंडक्टर मिशन को सपोर्ट करेगा , ओपन-सोर्स प्रोसेसर डेवलपमेंट , स्टार्टअप इनोवेशन और स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएशन को बढ़ावा देगा।
- 30 जुलाई से 1 अगस्त तक जोधपुर में इंटरनेशनल टाइप 1 डायबिटीज समिट 2026 होस्ट करेगा । फ्रेंड्स ऑफ मेवाड़, ब्रेकथ्रू T1D और विलियम जे. क्लिंटन फाउंडेशन द्वारा ऑर्गनाइज़ इस समिट में दुनिया भर के एक्सपर्ट्स सस्ते इंसुलिन, इंसुलिन पंप, डिजिटल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, लगातार ग्लूकोज मॉनिटरिंग और रिसर्च में सहयोग पर चर्चा करेंगे। इस इवेंट का मकसद टाइप 1 डायबिटीज केयर को बेहतर बनाना , इंटरनेशनल पार्टनरशिप को मजबूत करना और दुनिया भर में बेहतर मरीज़ों के नतीजों के लिए नए हेल्थकेयर सॉल्यूशन को बढ़ावा देना है।
- भारत के प्राइवेट स्पेस सेक्टर ने 31 मार्च 2026 तक कुल 618.5 मिलियन USD का इन्वेस्टमेंट किया , जो रिफॉर्म्स और इन्वेस्टर्स के भरोसे से हुई मज़बूत ग्रोथ को दिखाता है। 400 से ज़्यादा स्पेस स्टार्टअप्स अब सैटेलाइट मैन्युफैक्चरिंग, लॉन्च सर्विसेज़ और अर्थ ऑब्ज़र्वेशन में काम कर रहे हैं। IN- SPACe ने 105 ऑथराइज़ेशन जारी किए हैं , जबकि इंडिया स्पेस पॉलिसी 2023 और आसान FDI नॉर्म्स जैसी पॉलिसीज़ इनोवेशन को बढ़ावा देती हैं। यह बढ़ोतरी भारत के कमर्शियल स्पेस इकोसिस्टम, हाई-टेक मैन्युफैक्चरिंग, रोज़गार और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को मज़बूत करती है।
- चीन की प्राइवेट एयरोस्पेस कंपनी ओरिएनस्पेस ने ईस्ट चाइना सी में एक मैरीटाइम प्लेटफॉर्म से ग्रैविटी-1 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया , जिससे नौ सैटेलाइट ऑर्बिट में पहुंच गए। यह मिशन यांग्त्ज़ी रिवर डेल्टा से चीन का पहला कमर्शियल दूर-समुद्री लॉन्च और रॉकेट की तीसरी सफल उड़ान थी । ये सैटेलाइट अर्थ ऑब्ज़र्वेशन, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, मिनरल एक्सप्लोरेशन और एनवायरनमेंटल मॉनिटरिंग में मदद करते हैं । यह लॉन्च चीन के कमर्शियल स्पेस एम्बिशन को मज़बूत करता है और साथ ही भविष्य के ग्रैविटी-2 और ग्रैविटी-3 को भी आगे बढ़ाता है। कार्यक्रम .

महत्वपूर्ण दिन समाचार

- वर्ल्ड ब्रेन डे 2026, 22 जुलाई को “ब्रेन हेल्थ: एक्सेस फॉर ऑल” थीम के साथ मनाया गया । वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ न्यूरोलॉजी (WFN) के नेतृत्व में , यह कैंपेन न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर , जल्दी डायग्नोसिस, रोकथाम, इलाज, रिहैबिलिटेशन और ब्रेन हेल्थकेयर तक सभी की पहुंच के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देता है। स्ट्रोक, मिर्गी और माइग्रेन जैसी बीमारियों पर ज़ोर देते हुए , यह कैंपेन सरकारों और हेल्थकेयर सिस्टम को न्यूरोलॉजिकल सेवाओं को मजबूत करने और असमानताओं को कम करने के लिए प्रोत्साहित करता है। वर्ल्ड ब्रेन डे 2014 से हर साल मनाया जाता है ।
- 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय ध्वज (तिरंगा) को अपनाने की याद में 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस 2026 मनाया गया । यह दिन तिरंगे को आज़ादी, संप्रभुता, एकता और संवैधानिक मूल्यों के प्रतीक के रूप में मनाता है , साथ ही भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान का सम्मान भी करता है । केसरिया, सफ़ेद और हरे रंग का तिरंगा , जिसके बीच में अशोक चक्र है, साहस, शांति, समृद्धि और तरक्की को दिखाता है, और राष्ट्रीय ध्वज और उसके ऐतिहासिक महत्व का सम्मान करने के बारे में जागरूकता बढ़ाता है।

- लोकमान्य तिलक जयंती हर साल 23 जुलाई को भारत के सबसे महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक और राष्ट्रवादी आंदोलन के अग्रदूत बाल गंगाधर तिलक की याद में मनाई जाती है। "स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, और मैं इसे लेकर रहूँगा" नारे के लिए जाने जाने वाले तिलक ने स्व-शासन, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा और बड़े पैमाने पर लोगों की भागीदारी का समर्थन किया। उन्होंने डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी और फर्ग्यूसन कॉलेज जैसे संस्थान शुरू किए, केसरी और द मराठा को एडिट किया , सार्वजनिक गणेश उत्सव को लोकप्रिय बनाया , शिवाजी समारोहों को बढ़ावा दिया और एनी बेसेंट के साथ होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किया , जिससे भारत के स्वतंत्रता संघर्ष में एक स्थायी विरासत बनी।
- इनकम टैक्स डे 2026, 24 जुलाई को मनाया गया , जो 1860 में सर जेम्स विल्सन के इनकम टैक्स शुरू करने के 167 साल पूरे होने पर मनाया गया। सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ डायरेक्ट टैक्सेस (CBDT) 2010 से इसे मना रहा है , यह दिन देश बनाने में टैक्सपेयर्स के योगदान को पहचानता है और टैक्स कम्प्लायंस को बढ़ावा देता है । यह भारत के पेपर-बेस्ड एडमिनिस्ट्रेशन से डिजिटल टैक्सेशन में बदलाव को भी दिखाता है , जिसमें ऑनलाइन ITR फाइलिंग, फेसलेस असेसमेंट, पहले से भरे हुए रिटर्न और इनकम-टैक्स एक्ट, 1961 के तहत तेज़ रिफंड शामिल हैं।

Test Prime By Adda247

ALL EXAMS, ONE SUBSCRIPTION

Test. Analyze. Improve. Repeat.

Don't just prepare. Perform.

Test Prime – built only for mock tests.

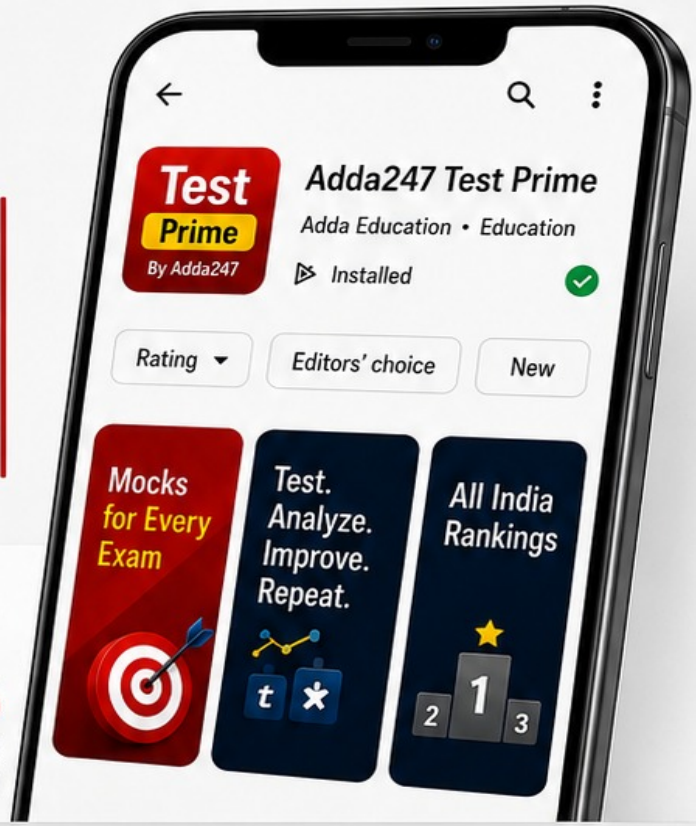

1,50,000+ Mock Tests

25,000+ Previous Year Papers

800+ Exam Covered

500% Refund on Selection

5 lakh+ Free Quizzes

Daily Free PDFs

Top Alerts Stay Updated

WHY TEST PRIME?

- Multilingual
- Detailed Solution
- Strong and Weak Areas
- All India Rankings

- Safe & Reliable
- Trusted by Lakhs of Aspirants
- Your Success, Our Mission

DOWNLOAD TEST PRIME

Your Success Partner!

GET IT ON Google Play

Download on the App Store